जनहितैषी

हिन्दी दैनिक

जनहितैषी अब janhitaishinews.com पर भी

R.N.I. No. 63177/95 वर्षः29 अंकः270 दिनांकः11-09-2024 बुधवार मूल्यः1 रूपया 50 पैसा पृष्ठः4 अहमदाबाद M

राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों और संग्रह का निर्धारण) संशोधन नियम, 2024 के नाम से अधिसूचित नए नियमों के तहत राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर 20 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करने पर ही वाहन मालिक से कुल दूरी पर शुल्क लिया जाएगा।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अमेरिका में सिख समुदाय पर की गई टिप्पणी को खतरनाक बताते हुए आलोचना की। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि राहुल ने विदेश में झूठ फैलाकर एक खतरनाक विमर्श गढ़ने की कोशिश की है।

अब 20 किमी. तक नहीं देना होगा शुल्क, इस नेविगेशन प्रणाली से लैस निजी वाहनों को राहत

नई दिल्ली (ईएमएस)।राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों और संग्रह का निर्धारण) संशोधन नियम, 2024 के नाम से अधिसूचित नए नियमों के तहत राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर 20 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करने पर ही वाहन मालिक से कुल दूरी पर शुल्क लिया जाएगा। सरकार ने टोल नियमों में बड़ा बदलाव किया है। इस राहत भरे बदलाव के जरिए अब जीएनएसएस से लैस निजी वाहनों को 20 किलोमीटर तक टोल टैक्स नहीं देना होगा। दरअसल, नए नियमों में कहा गया है कि वैश्विक नेविगेशन उपग्रह प्रणाली (जीएनएसएस) से लैस निजी वाहनों के मालिकों से राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर रोजाना 20 किलोमीटर तक के सफर के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।

इस संबंध में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मंगलवार को अधिसूचना जारी की है। इसमें राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों और संग्रह का निर्धारण) नियम, 2008 में संशोधन किया गया है। अब इसे राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों और संग्रह का निर्धारण) संशोधन नियम, 2024 के नाम से जाना जाएगा। नए नियमों के मुताबिक, राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेस-वे पर 20 किलोमीटर तक की दूरी तय करने पर कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। इससे अधिक की दूरी तय करने पर वाहन मालिक से कुल दूरी पर शुल्क लिया जाएगा।

अधिसूचना के मुताबिक, राष्ट्रीय परमिट रखने वाले वाहनों को छोड़कर अगर किसी अन्य वाहन का चालक या मालिक राष्ट्रीय राजमार्ग, स्थायी पुल, बाईपास या सुरंग के रूट का उपयोग करता है तो उससे जीएनएसएस-आधारित उपयोगकर्ता शुल्क संग्रह प्रणाली के तहत एक दिन में प्रत्येक दिशा में 20 किलोमीटर की यात्रा तक कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।

पायलट आधार पर लागू करने का फैसला किया था

इससे पहले मंत्रालय ने जुलाई में कहा था कि उसने फास्टैग के साथ एक अतिरिक्त सुविधा के रूप में चुनिंदा राष्ट्रीय राजमार्गों पर उपग्रह-आधारित टोल संग्रह प्रणाली को पायलट आधार पर लागू करने का फैसला किया है। जीएनएसएस-आधारित उपयोगकर्ता शुल्क संग्रह प्रणाली का एक पायलट अध्ययन कर्नाटक में एनएच-275 के बेंगलुरु-मैसूर खंड और हरियाणा में एनएच-709 के पानीपत-हिसार खंड पर किया गया है।

क्या है ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम?

उएए-आधारित टोल कलेक्शन सिस्टम के तहत हाईवे पर तय की गई दूरी के आधार पर टोल लिया जाता है। मौजूदा तरीके के तहत भले ही यूजर टोल रोड के एक हिस्से की यात्रा करता है, उसे एक निश्चित राशि का भुगतान करना पड़ता है। सैटेलाइट-आधारित सिस्टम वाहन की गतिविधि को ट्रैक करती है और वाहनों में लगे ऑन बोर्ड यूनिट की मदद से शुल्क की गणना करती है।

जीएनएसएस और जीपीएस में अंतर?

जीएनएसएस सैटेलाइट प्रणाली वह समूह है तो जो स्थिति और समय संबंधी संपूर्ण डेटा प्रदान करता है। वहीं, वैश्विक स्थान-निर्धारण प्रणाली (जीपीएस) जीएनएसएस के तहत आने वाले एक एक विशिष्ट प्रणाली है जो स्थान निर्धारित करने के लिए उपग्रहों का उपयोग करता है। गडकरी ने कहा था कि बहुत जल्द देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के लिए किसी और सब्सिडी की जरूरत नहीं होगी। आसान भाषा में समझें तो जीएनएसएस उपग्रहों का एक समूह है जो पृथ्वी पर मौजूद रिसीवर्स को डेटा प्रेषित करता है, वहीं जीपीएस उपग्रहों और रिसीवर्स का एक नेटवर्क हो किसी स्थान विशेष की जानकारी देता है।

विनेश और योगेश के बीच होगा मुकाबला

-भाजपा ने योगेश बैरागी जुलाना सीट से दिया टिकट

-जुलाना में 15 साल से नहीं जीत पाई है कांग्रेस

जींद (ईएमएस)। हरियाणा की जुलाना विधानसभा सीट से कैप्टन योगेश बैरागी (35) को टिकट मिल गया है। कैप्टन बैरागी एअर इंडिया से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (वीआरएस) ले चुके हैं और अब राजनीति में अपना कदम रख रहे हैं। जुलाना सीट पर उनका मुकाबला जाने-माने रेसलर और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विनेश फोगाट से होगा, जो इसी सीट से चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी कर रही हैं।

कैप्टन बैरागी की पृष्ठभूमि एयर इंडिया में रही है, जहां उन्होंने अपनी सेवाएं दीं और अब वह राजनीति के अखाड़े में कदम रख चुके हैं। जुलाना विधानसभा सीट पर मुकाबला दिलचस्प होने की उम्मीद है, क्योंकि यहां एक ओर खेल जगत की बड़ी हस्ती विनेश फोगाट हैं, तो दूसरी ओर पूर्व वायुसेना अधिकारी बैरागी।

जुलाना सीट पर चुनावी लड़ाई बेहद रोचक हो गई है। विनेश फोगाट, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कुश्ती में भारत का नाम रोशन कर चुकी हैं, अब राजनीति में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही हैं। वहीं, बैरागी का अनुभव और उनकी सादगी जनता के बीच खास पहचान बना रही है।

- जुलाना में 15 साल से नहीं जीत पाई है कांग्रेस

2009 और 2014 में इनेलो के परमिंदर सिंह ने इस सीट पर जीत दर्ज की और 2019 में जेजेपी के अमरजीत ढांडा ने जुलाना विधानसभा पर कब्जा किया। इस सीट पर जीत पाना विनेश के लिए भी चुनौतीपूर्ण होगा. स्पोर्ट्स स्टार और जाट चेहरे विनेश के कांग्रेस में आने से यह सीट हॉट सीट बन गई है। जुलाना सीट से कांग्रेस उम्मीदवार महिला पहलवान विनेश फोगाट के सामने भाजपा ने कैप्टन योगेश बैरागी को उतारा है। कैप्टन योगेश बैरागी ने डेढ़ साल पहले राजनीति में कदम रखा था। इससे पहले वे एयर इंडिया में सीनियर कैप्टन के पद पर कार्यरत थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना आदर्श मानने वाले कैप्टन योगेश ने भाजपा में शामिल होकर अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की।

विदेश में संवेदनशील मुद्दों पर बोलकर खतरनाक विमर्श गढ़ रहे राहुल;भाजपा

वॉशिंगटन(ईएमएस) भाजपा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अमेरिका में सिख समुदाय पर की गई टिप्पणी को खतरनाक बताते हुए आलोचना की। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि राहुल ने विदेश में झूठ फैलाकर एक खतरनाक विमर्श गढ़ने की कोशिश की है। कांग्रेस ने भाजपा के आरोपों को नकारते हुए कहा कि भाजपा राहुल की सच्चाई से घबराई हुई है और उनकी टिप्पणियों को विवादित बना रही है।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने अमेरिका में सिख समुदाय के बारे में राहुल गांधी की टिप्पणी को लेकर उन पर निशाना साधा। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने यहां भाजपा मुख्यालय में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि राहुल की टिप्पणी भयावह है, क्योंकि उन्होंने अपनी रोटियां सेकने के लिए विदेशों में रह रहे सिख समुदाय के सदस्यों के बीच झूठ फैलाने की कोशिश की। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष विदेश में 'संवेदनशील मुद्दों' पर बोलकर 'खतरनाक विमर्श' गढ़ने का प्रयास कर रहे हैं।

कांग्रेस ने अमेरिका में राहुल गांधी की टिप्पणियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के हमले पर पलटवार करते हुए मंगलवार को कहा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के सच बोलने से भाजपा का पूरा तंत्र घबराया और लड़खड़ाया हुआ है। कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने कहा कि जब हम सवाल देश में पूछते हैं, तो तब भी पूरा विश्व सुनता है, जब प्रधानमंत्री अटपटी बातें करते हैं, जब मन की बात करते हैं, जब कपड़ों से पहचानने की बात करते हैं, जब हिंदू-मुसलमान कर रहे होते हैं, तब भी पूरा विश्व सुनता है। क्या भाजपा को इतनी समझ नहीं है। खेड़ा ने कहा कि भाजपा हिजाब का विरोध करती है और आज हिजाब की बात है तो कल यह बात सिखों की पगड़ी तक पहुंच सकती है।

सिख समुदाय से ताल्लुक रखने वाले भाजपा नेता पुरी ने कहा कि सिखों के पगड़ी और कड़ा पहनने के बारे में राहुल की टिप्पणी की मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। कांग्रेस के शासनकाल में हुए 1984 के सिख विरोधी दंगों का जिक्र करते हुए पुरी ने कहा कि हमारे इतिहास में अगर कोई समय रहा है, जब एक समुदाय के रूप में हमने चिंता, असुरक्षा की भावना और अस्तित्व के खतरे को महसूस किया है तो यह ऐसा समय था जब राहुल गांधी का परिवार सत्ता में था।

कांग्रेस पार्टी सत्ता में आते ही आरक्षण खत्म कर देगी, राहुल के बयान के बाद मायावती की चेतावनी

लखनऊ (ईएमएस)। अमेरिकी दौरे पर गए राहुल गांधी ने कहा है कि जब कभी भारत निष्पक्ष होगा, तब कांग्रेस पार्टी आरक्षण खत्म करने के बारे में सोचेगी। इस पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि ओबीसी, एससी और एसटी वर्ग के लोग राहुल गांधी के इस नाटक से सतर्क रहें। कांग्रेस पार्टी सत्ता में आते ही आरक्षण खत्म कर देगी। संविधान और आरक्षण बचाने का नाटक करने वाली इस पार्टी से लोग जरूर सजग रहें। मायावती ने राहुल गांधी के बयान को लेकर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कई पोस्ट किए। उन्होंने लिखा है- केंद्र में काफी लम्बे समय तक सत्ता में रहते हुए कांग्रेस पार्टी की सरकार ने ओबीसी आरक्षण को लागू नहीं किया। देश में जातीय जनगणना कराने की आड़ में यह पार्टी सत्ता में आने के सपने देख रही है। इनके इस नाटक से सचेत रहें जो आगे कभी भी जातीय जनगणना नहीं करा पाएगी। अब कांग्रेस पार्टी के सर्वेसर्वा राहुल गांधी के इस नाटक से भी सर्तक रहें जिसमें उन्होंने विदेश में यह कहा है कि भारत जब बेहत्तर स्थिति में होगा तो हम आरक्षण खत्म कर देंगे। इससे स्पष्ट है कि कांग्रेस वर्षो से इनके आरक्षण को खत्म करने के षडयंत्र में लगी है।

मायावती आगे लिखती हैं- इन वर्गों के लोग कांग्रेसी नेता राहुल गांधी के दिए गए इस घातक बयान से सावधान रहें, क्योंकि यह पार्टी केन्द्र की सत्ता में आते ही, अपने इस बयान की आड़ में इनका आरक्षण जरूर खत्म कर देगी। लोग संविधान और आरक्षण बचाने का नाटक करने वाली इस पार्टी से जरूर सजग रहें। जबकि सच्चाई में कांग्रेस शुरू से ही आरक्षण-विरोधी सोच की रही है। केंद्र में रही इनकी सरकार में जब इनका आरक्षण का कोटा पूरा नहीं किया गया तब इस पार्टी से इनको इंसाफ ना मिलने की वजह से ही बाबा साहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर ने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। लोग सावधान रहें।

बसपा सुप्रीमो ने कहा कि जब तक देश में जातिवाद जड़ से खत्म नहीं हो जाता है तब तक भारत की स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर होने के बावजूद भी इन वर्गों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक हालत बेहतर होने वाली नहीं है। अतः जातिवाद के समूल नष्ट होने तक आरक्षण की सही संवैधानिक व्यवस्था जारी रहना जरूरी है।

ओटीटी प्लेटफॉर्म रेगुलेट किए जाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल

नई दिल्ली (ईएमएस)। देश में ओटीटी प्लेटफॉर्म को रेगुलेट किए जाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई याचिका में ओटीटी और स्ट्रीमिंग प्लेटफ़ॉर्म की निगरानी और प्रबंधन के लिए एक रेगुलेटरी बोर्ड बनाने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट के वकील शशांक शेखर झा ने याचिका दाखिल की है।

याचिका में कहा गया है कि सिनेमाघरों में दिखाई जाने वाली फ़िल्मों के विपरीत, ओटीटी कंटेंट रिलीज़ से पहले सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया से नहीं गुज़रते हैं। ?जिसके कारण ओटीटी पर अक्सर उचित चेतावनी के बिना ही अश्लील दृश्य, हिंसा, नशीले पदार्थों के सेवन और अन्य हानिकारक सामग्री में वृद्धि हुई है।

याचिका में कहा गया है कि सरकार ने आईटी कानून 2021 को सरकार ने बनाया लेकिन इस नियम का कोई असर ओटीटी कंटेंट पर नहीं पड़ा है। ये प्लेटफ़ॉर्म नियमों की खामियों का फ़ायदा उठाते रहते हैं। बिना किसी जांच के विवादास्पद सामग्री डालते रहते हैं। ?जिसका राष्ट्रीय सुरक्षा पर असर पड़ता है और जुआ और ड्रग्स जैसी चीज़ों को बढ़ावा मिलता है।

राहुल गांधी के बयान से साफ..........आरक्षण-विरोधी हैं कांग्रेसः मायावती का आरोप

लखनऊ (ईएमएस)। बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) की अध्यक्ष मायावती ने आरक्षण खत्म करने को लेकर टिप्पणी करने वाले कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर हमला कर कहा कि राहुल गांधी के इस बयान से स्पष्ट है कि उनकी पार्टी वर्षों से अनुसूचित जातियों (एससी), अनुसूचित जनजातियों (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) का आरक्षण खत्म करने की साजिश में गुपचुप तरीके से लगी है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने जॉर्जटाउन विश्वविद्यालय में छात्रों से संवाद कार्यक्रम में भारत में आरक्षण कब तक जारी रहेगा, इस पर राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी आरक्षण खत्म करने के बारे में तब सोचेगी, जब भारत में आरक्षण के लिहाज से निष्पक्षता होगी लेकिन अभी ऐसा नहीं है।

मायावती ने कहा, ''केन्द्र में लंबे समय तक सत्ता में रहते हुए कांग्रेस पार्टी नीत सरकार ने ओबीसी आरक्षण को लागू नहीं किया और ना ही देश में जातीय जनगणना होने दी। अब कांग्रेस (जातिवार जनगणना) आड़ में सत्ता में आने के सपने देख रही है। इनके इस नाटक से सचेत रहें जो भविष्य में कभी जातीय जनगणना नहीं करा पाएगी।

मायावती ने कहा, ''अब कांग्रेस के सर्वेसर्वा राहुल गांधी के इस नाटक से भी सतर्क रहें, जिसमें उन्होंने विदेश में कहा है कि भारत जब बेहतर स्थिति में होगा तब हम एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। इससे स्पष्ट है कि कांग्रेस वर्षों से इनके आरक्षण को खत्म करने के षडयंत्र में लगी है। उन्होंने कहा, इन वर्गों के लोग कांग्रेस नेता राहुल गांधी के दिए गए घातक बयान से सावधान रहें, क्योंकि यह पार्टी केंद्र की सत्ता में आते ही, अपने इस बयान की आड़ में इनका आरक्षण जरूर खत्म कर देगी। ये लोग संविधान व आरक्षण बचाने का नाटक करने वाली इस पार्टी से जरूर सजग रहें।

मायावती ने कहा, सचाई सिर्फ इतना हैं कि कांग्रेस शुरू से ही आरक्षण-विरोधी सोच की रही है। केंद्र में कांग्रेस सरकार में जब आरक्षण का कोटा पूरा नहीं किया गया तब कांग्रेस पार्टी से इस वर्ग (एससी, एसटी, ओबीसी) के लोगों को इंसाफ नहीं मिल पाने की वजह से ही बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आंबेडकर ने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। लोग सावधान रहें। उन्होंने कहा, ''कुल मिलाकर, जब तक देश में जातिवाद जड़ से खत्म नहीं हो जाता है तब तक भारत की स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर होने के बावजूद इन वर्गों के लोगों की सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक हालत बेहतर होने वाली नहीं है। इसलिए जातिवाद के समूल नष्ट होने तक आरक्षण की सही संवैधानिक व्यवस्था जारी रहना जरूरी।

राष्ट्रपति ने लिया बीजेपी के पत्र पर संज्ञान, क्या दिल्ली में लगेगा राष्ट्रपति शासन?

नई दिल्ली,(ईएमएस)। राष्ट्रपति द्रोपदी मूर्मू ने दिल्ली की आम आदमी सरकार को बर्खास्त करने की मांग करने संबंधी दिल्ली बीजेपी की अपील को गृह मंत्रालय के पास भेज दिया है। इस संबंध में दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि संविधान के कथित उलंघन के लिए आम आदमी पार्टी (आप) सरकार को बर्खास्त किए जाने की मांग बीजेपी के विधायकों द्वारा राष्ट्रपति को सौंपा गया ज्ञापन गृह मंत्रालय को भेज दिया गया है। विजेंद्र ने दावा किया है कि दिल्ली सरकार द्वारा छठे दिल्ली वित्त आयोग का गठन नहीं करना और कैग रिपोर्ट पर कार्रवाई न करना संविधान का उल्लंघन है।

बता दें कि बीजेपी विधायकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने 30 अगस्त को राष्ट्रपति से मुलाकात कर एक ज्ञापन सौंपा था जिसमें दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के जेल में होने के कारण दिल्ली में उत्पन्न संवैधानिक संकट के बीच तत्काल हस्तक्षेप करने का आग्रह किया था। विजेंद्र ने राष्ट्रपति सचिवालय से प्राप्त पत्र को साझा करते हुए कहा कि राष्ट्रपति ने ज्ञापन पर संज्ञान लेते हुए उसे गृह सचिव को भेज दिया है। उन्होंने कहा कि गृह सचिव से इस मामले पर तत्काल और उचित कार्रवाई करने का आग्रह किया है।

हेमा समिति की रिपोर्ट के आधार पर एक्शन क्यों नहीं......केरल सरकार को फटकार

तिरुअनंतपुरम (ईएमएस)। केरल उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार पर न्यायमूर्ति हेमा समिति की रिपोर्ट के आधार पर निष्क्रियता और मामले दर्ज न करने के लिए कड़ी फटकार लगा दी। इस रिपोर्ट में मलयालम फिल्म उद्योग में महिलाओं के यौन शोषण को उजागर किया था। न्यायमूर्ति ए.के. जयशंकरन नांबियार और न्यायमूर्ति सी.एस. सुधा की एक विशेष पीठ ने सरकार द्वारा गठित एसआईटी को कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया, हालांकि इसने मीडिया को चुप कराने से इंकार कर दिया।

यह देखकर कि रिपोर्ट 2019 में ही सरकार को सौंप दी गई थी, अदालत ने कहा, हम मुख्य रूप से राज्य की निष्क्रियता से चिंतित हैं, जिसमें एफआईआर दर्ज न करना भी शामिल है... 4 साल में रिपोर्ट को दबाए रखने के अलावा कुछ नहीं किया है। अदालत ने कहा कि सरकार के लिए चुप्पी कोई विकल्प नहीं है और इस बात पर जोर दिया कि महिलाओं के खिलाफ पूर्वाग्रह और भेदभाव को बदलना होगा।

उच्च न्यायालय ने कहा, समाज में महिलाओं के सामने आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए आप क्या कर रहे हैं? सिर्फ फ़िल्म उद्योग ही नहीं। स्थिति खराब है और वह भी हमारे जैसे राज्य में। हमारे राज्य में महिलाओं की आबादी ज़्यादा है। यह हमारे लिए अल्पसंख्यक मुद्दा नहीं है... एसआईटी को इस सब पर गौर करना चाहिए।

केरल सरकार ने 2017 में जस्टिस हेमा समिति का गठन किया था। 19 अगस्त, 2024 को सार्वजनिक की गई रिपोर्ट में मलयालम फ़िल्म उद्योग में महिलाओं के उत्पीड़न और शोषण के मामलों का खुलासा किया गया है।अदालत ने कहा कि सरकार के लिए चुप्पी कोई विकल्प नहीं है और इस बात पर जोर दिया कि महिलाओं के खिलाफ पूर्वाग्रह और भेदभाव को बदलना होगा।

पश्चिम बंगाल में आंदोलनकारी जूनियर डॉक्टरों ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश को नहीं माना, आंदोलन जारी रहेगा

नई दिल्ली (ईएमएस)। पश्चिम बंगालमें आंदोलनकारी जूनियर डॉक्टरों ने कामपर लौटने सी इनकार कर दिया है। इस सम्बन्ध में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश की अवज्ञा करते हुए डॉक्टरों ने कहा कि वे अपनी मांगें पूरी होने और आरजी कर अस्पताल घटना की पीड़िता को न्याय मिलने तक डयूटी पर नहीं जाएंगे। ज्ञात रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने एक दिन पहले, प्रदर्शनकारी रेजिडेंट डॉक्टरों को मंगलवार शाम पांच बजे तक काम पर लौटने का निर्देश देते हुए कहा था कि ऐसा करने पर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।

आंदोलनकारी डॉक्टरों ने कहा है कि हमारी मांगें पूरी नहीं होने के कारण हम काम बंद रखेंगे। हमने राज्य सरकार को कोलकाता पुलिस आयुक्त, स्वास्थ्य सचिव, स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशक और चिकित्सा शिक्षा निदेशक को शाम पांच बजे तक पद से हटाने को कहा था। हम चर्चा के लिए तैयार हैं।

लालबाजार स्थित कोलकाता पुलिस मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन करने के एक सप्ताह बाद, सैकड़ों जूनियर चिकित्सकों ने मंगलवार को स्वास्थ्य भवन की ओर मार्च किया और आर जी कर अस्पताल में बलात्कार एवं हत्या की पीड़िता चिकित्सक के लिए न्याय की मांग की। इसके साथ ही प्रदर्शनकारी चिकित्सकों ने मामले में कोलकाता के पुलिस आयुक्त एवं कई स्वास्थ्य अधिकारियों के इस्तीफे की मांग की। प्रदर्शनकारी डॉक्टर पिछले सप्ताह लालबाजार में रीढ़ की हड्डी का मॉडल लेकर गए थे। इस बार प्रदर्शनकारी डॉक्टरों ने साल्ट लेक के सेक्टर-5 में पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य विभाग के मुख्यालय की ओर मार्च करते हुए झाड़ू और मस्तिष्क का मॉडल दिखाया।

आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल ने51डॉक्टरों को नोटिस जारी किया है और उन्हें 11सितंबर को जांच समिति के समक्ष पेश होने के लिए कहा है। अस्पताल के अधिकारियों द्वारा जारी नोटिस में कहा गया है कि उन्हें समिति के समक्ष अपनी बेगुनाही साबित करनी होगी। आरजी कर अस्पताल की विशेष परिषद समिति द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार, उन 51 डॉक्टरों के लिए संस्थान के परिसर में प्रवेश प्रतिबंधित है, जब तक कि जांच समिति द्वारा उन्हें नहीं बुलाया जाता।

अस्पताल के प्राचार्य द्वारा हस्ताक्षरित नोटिस में कहा गया है इन डॉक्टरों के कॉलेज की गतिविधियों में भाग लेने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। सूची में वरिष्ठ रेजिडेंट, हाउस स्टाफ, इंटर्न और प्रोफेसर शामिल हैं।

हसीना के तमाम फैसलों को पलट रही यूनुस सरकार,हिलसा पर लगाया प्रतिबंध

ढाका(ईएमएस)। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना द्वारा लिए गए तमाम फैसलों का यूनुस सरकार अध्ययन कर रही है। अब तक कई फैसले पलट दिए गए हैं और कईयों को बहुत जल्द पलट दिया जाएगा। इस बीच दुर्गा पूजा के शुरू होने से कुछ दिन पहले ही बांग्लादेश ने एक ऐसा फैसला लिया, जिसका असर भारत पर पड़ने वाला है। दरअसल, बांग्लादेश सरकार ने हिलसा मछली के निर्यात पर बैन लगा दिया है। अब दुर्गा पूजा से कुछ दिन पहले आए इस फैसले का बंगाली लोगों पर खासा असर पड़ेगा। इस फैसले के बाद बंगाल में हिलसा यानी बांग्लादेशी इलिश (बंगाली में कहा जाता है) के दाम काफी चढ़ गए हैं और अब मछली को खरीदने के लिए ज्यादा जेब ढीली करनी पड़ रही है।

दूसरी ओर शेख हसीना सरकार के समय पर हिलसा मछली के निर्यात को आसान बनाया गया था। हालांकि, ये बैन भारत पर ज्यादा असर नहीं डालेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत ने दूसरा रास्ता खोज लिया है। बांग्लादेश से आने वाली हिल्सा अब म्यांमार के रास्ते भारत आ रही है। लेकिन अब इसके लिए ग्राहकों को ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे। कुछ महीने पहले एक किलो हिलसा की कीमत 1800 रुपये तक थी, जो अब 2400 तक पहुंच गई है। बांग्लादेश सरकार ने इस फैसले पर सफाई देते हुए कहा कि स्थानीय लोगों के लिए हिलसा की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के यह फैसला लिया गया है। बांग्लादेश के मत्स्य पालन और पशुधन मंत्रालय की सलाहकार फरीदा अख्तर ने कहा कि अगर निर्यात पर बैन नहीं लगाया जाता तो देश में हिलसा के दाम काफी बढ़ जाते।बता दें कि इलिश मछली का 70 फीसद उत्पादन केवल बांग्लादेश में होता है, जिसके चलते पड़ोसी मुल्क को काफी फायदा होता है।

मणिपुर यूनिवर्सिटी में होने वाले यूजी और पीजी के सभी एग्जाम टले

इम्फाल (ईएमएस)। हिंसा की आशंका के चलते मणिपुर यूनिवर्सिटी में होने वाले यूजी और पीजी के सभी एग्जाम को टाल दिया गया है। वहीं राज्य के तीन जिलों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। अधिकारियों ने इंफाल पूर्व, इंफाल पश्चिम और थौबल में फिर से कर्फ्यू लगाया है। राज्य में बढ़ती हिंसा के खिलाफ मणिपुर के मुख्यमंत्री सचिवालय और इंफाल में राजभवन के सामने प्रदर्शन कर रहे सैकड़ों छात्र फिर से इमा मार्केट (नुपी कीथेल) में जमा हो गए। वह दोबारा अपनी मांगों को लेकर एक जगह पर एकत्रित हुए हैं। इसके साथ ही सरकार ने 5 दिनों के लिए राज्य के 5 जिलों में इंटरनेट को बंद कर दिया है।

राज्य के गृह विभाग ने एक अधिसूचना में कहा कि यह निर्णय तस्वीर, नफरती भाषण और नफरती वीडियो के प्रसार के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर अंकुश लगाने के लिए लिया गया है। अधिसूचना में कहा गया है, ''मणिपुर राज्य के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में 10 सितंबर को अपराह्न 3 बजे से 15 सितंबर को अपराह्न 3 बजे तक पांच दिनों के लिए लीज लाइन, वीसैट, ब्रॉडबैंड और वीपीएन सेवाओं सहित इंटरनेट और मोबाइल डेटा सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित/रोकने का आदेश दिया गया है।

जल्द ही लिथियम-आयन बैटरी निर्यात करेगा भारतः गडकरी

मुंबई (ईएमएस)। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि भारत जल्द ही लिथियम-आयन बैटरी निर्यात करने की स्थिति में आ जाएगा। रिचार्जेबल बैटरी जो इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के लिए आवश्यक हैं। केंद्रीय मंत्री गडकरी ने कहा कि ईवी वृद्धि के आंकड़े काफी उत्साहजनक और ये भारत ऑटोमोबाइल ताकत को दिखाते हैं।

मंगलवार को सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (सियाम) के 64वें सम्मेलन में गडकरी ने उम्मीद जाहिर कि 2030 तक ईवी बाजार में 1 करोड़ की बिक्री होगी। उन्होंने अनुमान लगाया कि 2030 तक ईवी फाइनेंस बाजार 5 लाख करोड़ रुपये का होगा।

गडकरी ने कहा कि वे पेट्रोल और डीजल के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन मेरा मानना है कि लोगों को प्रदूषण से सुरक्षा की जरूरत है। गडकरी स्वच्छ ईंधन पर जोर देने और वाहन निर्माताओं से ईवी और हाइड्रोजन पर ध्यान देने का आग्रह करने के लिए जाने जाते हैं। गडकरी ने उद्योग से नई तकनीक अपनाने और पेट्रोल और डीजल के बारे में चिंता न करने का आग्रह किया।

पिछले सप्ताह गडकरी ने कहा था कि बहुत जल्द देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के लिए किसी और सब्सिडी की जरूरत नहीं होगी। पिछले सप्ताह गडकरी ने कहा था कि लिथियम-आयन बैटरी की कीमत जो पहले 150 डॉलर प्रति किलोवाट प्रति घंटा हुआ करती थी, अब घटकर 107-108 डॉलर प्रति किलोवाट प्रति घंटा रह गई है। उन्होंने कहा था कि पांच कंपनियों ने लिथियम-आयन बैटरी का निर्माण शुरू कर दिया है और अगले कुछ वर्षों में इसकी कीमत कम होकर 90 डॉलर प्रति किलोवाट प्रति घंटा रह जाएगी। डीजल और पेट्रोल वाहनों और इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमत बराबर होगी, लेकिन बिजली की कीमत जीवाश्म ईंधन से 10 गुना कम होगी।

वक्फ संशोधन बिल पर जहर उगल रहा भगौड़ा जाकिर....50 लाख मुसलमान साथ आए

नई दिल्ली (ईएमएस)। वक्फ संशोधन बिल पर छिड़ी जंग में अब कट्टरपंथी जाकिर नाइक की भी एंट्री हो गई है। भगौड़ा जाकिर जहर उगल रहा है। जाकिर कह रहा है कि वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ एकजुट हो जाओ। वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की हिफाजत करो। मुसलमानों की भावी पीढ़ियों के लिए लड़ने का आह्वान जाकिर नाइक की ओर से हो रहा है। जाकिर ने कहा है कि करीब 50 लाख मुसलमान एक साथ आ जाए और वक्फ संशोधन बिल के रिजेक्शन पर क्लिक करें। इसके लिए स्कैन अभियान भी शुरू कर दिया है। जितने लोग मुहिम में हिस्सा लेते हैं उनका मत संयुक्त संसदीय कमेटी तक पहुंचाया जाएगा।

दरअसल, वक्फ बिल के खिलाफ इन दिनों कई मुस्लिम संगठन मुहिम चला रहे हैं। जाकिर इस मुहिम को हाईजैक कर खुद को मुसलमानों का असली रहनुमा साबित करना चाहता है। जाकिर कह रहा है कि करीब पचास लाख मुसलमानों को बिल के खिलाफ उसके अभियान से जुड़ना चाहिए। लेकिन इसके पीछे उसका असली मंसूबा 50 लाख मुसलमानों को उसके जहरीले एजेंडे से जोड़ना हो सकता है।

मलेशिया में रहकर जाकिर भारत के खिलाफ कट्टरपंथी एजेंडा चलाता है। नफरत फैलाने और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के बीच 2016 में भारत से भाग गया था। इस्लामिक उपदेशक को पिछली महाथिर मोहम्मद सरकार द्वारा मलेशिया में स्थायी निवास की अनुमति दी गई थी, जिससे भारत को काफी निराशा हुई थी। नाइक को कई बार अनवर इब्राहिम के साथ देखा गया है। इसके बाद अनवर इब्राहिम के इस दौरे पर जाकिर नाइक के वापसी की मांग उठने लगी है।

जहां तक वक्फ बोर्ड बिल के विरोध का सवाल है, तब असदद्दीन ओवैसी जैसे नेता पहले से अभियान चला रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी दिल्ली में बैठकर वक्फ बोर्ड पर कानून बनाएंगे। अब वक्फ को कोई एक्शन लेना है, तब पीएम नरेंद्र मोदी से पूछना पड़ेगा।

वियतनाम में यागी तूफान में टूटा स्टील पुल, कई गाड़ियां और लोग बहे

बिजली सप्लाई ठप, 15 लाख लोग अंधेरे में रहे रहने को मजबूर

हनोई,(ईएमएस)। वियतनाम में आए सुपर टाइफून यागी तूफान ने भारी तबाही मचाई है। उत्तरी वियतनाम में तूफान के कारण एक पुल ढह गया है। वहीं भूस्खलन के कारण 60 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। पुल के गिरने का वीडियो सामने आया है। फुटेज में दिख रहा है कि फू थो प्रांत में फोंग चाऊ पुल पानी में ढह गया। इस कारण कार के आगे चल रहे कई वाहन पानी में डूब गए। एक ट्रक भी गिरता दिख रहा है। 13 लोगों लापता बताए जा रहे हैं उनकी तलाश की जा रही है। तूफान से बिजली सप्लाई ठप हो गई है और 15 लाख लोग बिना बिजली के रह रहे हैं।

मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है कि 247 लोग घायल हुए हैं। इनमें से 157 क्वांग मिन्ह प्रांत से और 40 लोग हाई फोंग शहर के हैं। आपदा में 25 नौकाएं और जहाज डूब गए है, जिनमें से ज्यादातर मछली पकड़ने वाली नावें थीं। इस आपदा से 1,13,000 हेक्टेयर चावल के खेत और 22 हजार हेक्टेयर से ज्यादा अन्य फसलों को नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा 1,90,000 पक्षी मारे गए और करीब 1,21,700 पेड़ नष्ट हो गए। वियतनाम के उत्तरी फू थो प्रांत में स्टील पुल ढहने से कारण 10 गाड़ियां और दो बाइक रेड नदी में गिर गईं और 13 लोग लापता हो गए।

स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक काओ बांग प्रांत में भूस्खलन के कारण 21 लोगों की मौत हो गई और कई लापता हैं। वहीं, लाओ कै प्रांत में 15 लोगों की मौत हुई है। मंत्रालय के मुताबिक तूफान के कारण वियतनाम के हालत पूरी तरह से खराब हैं। वियतनाम में यह 30 सालों में सबसे शक्तिशाली तूफान है।

जन हितैषी

विश्वास की कड़ी टूटते ही मणिपुर में हिंसा

एक बार फिर मणिपुर हिंसा की आग में झुलस रहा है। पिछले 11 दिनों में 8 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। दोनों ही समुदाय एक दूसरे के ऊपर हमला कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी मणिपुर के मुख्यमंत्री और राज्यपाल का इस्तीफा मांग रहे हैं। स्कूली छात्र अब इस आंदोलन में शामिल हो गए हैं। स्कूली छात्रों ने इंफाल में सीआरपीएफ के जवानों पर भी हमला कर दिया। मणिपुर का राजभवन भी अब सुरक्षित नहीं रहा। यहां पर आंदोलनकारियों द्वारा पथराव किया जा रहा है। स्थानीय नागरिक कुकी हों या मेतई, दोनों ही ड्रोन और रॉकेट के हमलों से भयभीत हैं। राज्य सरकार दोनों ही समुदाय को सुरक्षा नहीं दे पा रही है। केंद्र सरकार ने 50000 से अधिक सुरक्षाबल मणिपुर में तैनात कर रखा है। वह भी कुकी और मेतई समुदाय का विश्वास नहीं जीत पाई है। मुख्यमंत्री बीरेन सिंह के खिलाफ अब मैतई समुदाय में भी भारी रोष देखने को मिल रहा है। स्कूली छात्रों ने अपनी छह सूत्री मांगों को रखा था। जिस पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने कोई प्रतिक्रिया न देते हुए, छात्रों को टाल दिया। इससे छात्रों का गुस्सा भड़क गया है। छात्र सड़कों पर उतर आए हैं। मेतई संगठनों ने सरकारी कार्यालय में अपना झंडा फहरा दिया। आंदोलनकारियों का कहना है, सुरक्षा सलाहकार और डीजीपी राज्य में शांति स्थापित करने में असफल रहे हैं। आंदोलनकारी उन दोनों के साथ, मुख्यमंत्री और राज्यपाल को भी हटाने की मांग कर रहे हैं।

16 महीने से मणिपुर में हिंसा चल रही है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सुप्रीम कोर्ट सभी ने अपने-अपने स्तर पर प्रयास किया। मणिपुर की देश और विदेशों में चर्चा हो रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी दो बार मणिपुर का दौरा कर चुके हैं। इसके बाद भी मणिपुर में शांति स्थापित नहीं हो पा रही है। इसका मूल कारण हाईकोर्ट के आरक्षण पर दिए गए निर्णय के बाद से, मणिपुर घाटी सुलग रही है। आरक्षण विवाद की चिंगारी मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने लगाई थी। आरक्षण के मुद्दे पर मेतई समुदाय का समर्थन प्रारंभ में मणिपुर के मुख्यमंत्री को मिल रहा था। लेकिन अब मेतई समुदाय भी उनसे नाराज है। मुख्यमंत्री के होते हुए इस समुदाय को काफी बड़ा नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री बीरेन सिंह मैतई समुदाय की रक्षा नहीं कर पाए। लाखों की संख्या में मेतई समुदाय की महिलाएं और बच्चे परेशान हैं। मणिपुर की पूर्व राज्यपाल अनसुईया उइके दोनों ही समुदाय के बीच विश्वास की कड़ी बनी थीं। मणिपुर की सामाजिक व्यवस्था में महिलाओं का वर्चस्व है। मणिपुर की पूर्व राज्यपाल ने दोनों समुदाय के बीच विशेषकर महिलाओं के बीच समन्वय बनाने में सफलता पाई थी। वह दोनों ही समुदाय के लोगों से मिलकर उनका भरोसा जगा रही थीं। विवाद को सुलझाने में वह दोनों पक्षों का भरोसा जीतने में सफल रही हैं। जैसे ही उनका कार्यकाल खत्म हुआ। अगस्त माह में वह गवर्नर का पद छोड़कर वापस चली गईं। उसके बाद से मणिपुर के लोगों में विश्वास का संकट पैदा हो गया है। पूर्व राज्यपाल अनसुईया उइके के रहते हुए दोनों समुदायों को विश्वास था, जल्द ही मणिपुर में शांति स्थापित होगी। जैसे ही अनुसुईया उइके मणिपुर छोड़कर गई हैं। उसके बाद से ही मणिपुर में हिंसा का नया दौर शुरू हो गया। मणिपुर में जब तक बीरेन सिंह मुख्यमंत्री बने रहेंगे, तब तक मणिपुर की समस्या का समाधान नहीं होगा। वही आग में पेट्रोल डालने का काम कर रहे हैं। केंद्र सरकार की नीतियां और शांति के प्रयास मुख्यमंत्री के कारण मणिपुर में सफल नहीं हो पा रहे हैं। मुख्यमंत्री बीरेन सिंह पर दोनों ही समुदाय को अब कोई विश्वास नहीं है। रही सही कसर जो नए कार्यवाहक राज्यपाल आए हैं, वह भी मुख्यमंत्री के नक्शे-कदम पर चलकर पूरी कर रहे हैं। इस कारण मणिपुर की स्थिति दिनों दिन खराब होती जा रही है। दोनों ही समुदाय के लोगों में डर और भय का वातावरण बना हुआ है। पूर्व राज्यपाल अनसुईया उईके जरूर एक विश्वास का प्रतीक थी। उनके मणिपुर में नहीं होने से अब डर और भय का वातावरण बन गया है। ऐसी स्थिति में मणिपुर में शांति स्थापित हो पाना नामुमकिन है। केंद्र सरकार ने मणिपुर को एक तरह से मुख्यमंत्री के हवाले कर दिया है। जिसके कारण केंद्र और राज्य सरकार के प्रति मणिपुर के दोनों समुदायों में भयंकर नाराजी है। केंद्र सरकार को समय रहते, मणिपुर के मुख्यमंत्री को बर्खास्त कर, निष्पक्ष प्रशासन को तैनात करना होगा। जो दोनों ही पक्षों का विश्वास जीत सके। मणिपुर के मामले में केंद्र सरकार को पूर्व राज्यपाल अनसुइया उइके का भी उपयोग मणिपुर में शांति स्थापित करने में करना चाहिये। दोनों समुदाय को उनके ऊपर विश्वास है। विश्वास के जरिए ही दोनों समुदाय के बीच बातचीत हो सकती है। स्थितियों का समाधान निकाला जा सकता है। केंद्र सरकार को इस मामले में गंभीरता से विचार कर, तुरंत निर्णय लेने की जरूरत है। अनिर्णय की स्थिति में सीमावर्ती राज्य, पूर्वोत्तर राज्यों एवं देश की सुरक्षा को लेकर गंभीर संकट उत्पन्न हो सकते हैं।

जम्मू-कश्मीर पर रक्षामंत्री का दूरगामी सन्देश

जम्मू-कश्मीर में चुनाव प्रचार को एक नई करवट देते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ऐसी बातें कहीं है जो घाटी के लोगों के दिलों को छूने वाली होने के साथ प्रांत में नई उम्मीदों के नये दौर का आगाज है एवं गुलाम कश्मीर के लोगों के प्रति सहानुभूति एवं आत्मीयता दर्शाने वाली है। एक दिन पहले करगिल युद्ध को लेकर पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने वो बात कुबूल कर ली, जो अब तक सारे पाकिस्तानी जनरल पूरी दुनिया से छिपाते रहे। आसिम मुनीर ने साफ-साफ कहा कि कारगिल जंग में पाकिस्तानी सेना का हाथ था। उनके सैनिकों ने शहादत दी है। इसके अगले ही दिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का जम्मू-कश्मीर की धरती से ये ऐलान कि अगर पाकिस्तान आतंक छोड़ दे तो उसके साथ बातचीत हो सकती है। यह बयान बहुत कुछ कहता है एवं इसके कई दूरगामी राजनीतिक दृष्टिकोण है। पाकिस्तान समझ चुका है कि कश्मीर में अब उसका कुछ नहीं बचा। रही सही कसर, जम्मू-कश्मीर में हो रहे चुनावों में लोगों की जोरदार भागीदारी ने पूरी कर दी। उसकी सारी उम्मीदों पर पानी फिरता दिख रहा है, ऐसे में वह हकीकत स्वीकार करता नजर आ रहा है। रक्षामंत्री की कही बातों में पाकिस्तान सरकार को सीधा सन्देश दिया गया है। निश्चित ही राजनाथ सिंह के बयान एक अनुभवी एवं कद्दावर नेता के रणनीतिक एवं दूरगामी सोच से जुड़े बयान है, जिनकी प्रतिक्रिया दोनों ही देशों में होने के साथ ही चुनाव में हिस्सेदारी कर रहे राजनीतिक दलों में सुगबुगाहट का बड़ा कारण बना है।

कश्मीर में विकास, पर्यटन में भारी वृद्धि, शांति एवं सौहार्द का वातावरण बनना गुलाम कश्मीर के लोगों को प्रेरित कर रही हैं कि उन्हें भी इस ओर आजाद फिजा में सांस लेने का मौका मिले। ऐसे में रक्षामंत्री ने उन्हें भारत का हिस्सा बनने का निमंत्रण देकर पड़ौसी देश की दुखती रग को छेड़ दिया है एवं पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है, बल्कि गुलाम कश्मीर के लोगों में भी नया विश्वास एवं मनोबल जगा दिया है। रक्षामंत्री का यह निमंत्रण बहुत मायने रखता है, इससे पहले गृहमंत्री अमित शाह ने भी कहा था कि गुलाम कश्मीर हमारा है एवं हम इसे लेकर रहेंगे। गुलाम कश्मीर के लोग भारत से मिलने के लिये उत्सुक है, आन्दोलनरत है। क्योंकि पाकिस्तानी शासक उन्हें विदेशियों की तरह देखते हैं। यह एक सच्चाई भी है। पाकिस्तान अपने कब्जे वाले कश्मीर के लोगों का जैसा दमन और शोषण कर रहा है, उसके कई प्रमाण सामने आ चुके हैं। इसी दमन और शोषण के चलते जब-तब वहां पाकिस्तान के खिलाफ सड़कों पर उतरकर लोग भारत जाने की अनुमति भी मांगते रहते हैं। गुलाम कश्मीर में आंदोलन का नेतृत्व कर रहे लोगों को मारा जा रहा है। वहां के लोग यह अच्छी तरह देख रहे हैं कि भारतीय भूभाग में किस तरह तेजी से विकास हो रहा है और उन्हें किस तरह पाकिस्तान की ओर से ठगा जाता रहा है। कहना कठिन है कि रक्षा मंत्री के बयान पर पाकिस्तान क्या कहता है, लेकिन इसके आसार कम ही हैं कि वह आतंकवाद को सहयोग-समर्थन देने से बाज आएगा। पाकिस्तान की दमनकारी नीतियों के खिलाफ आंदोलन कर रहे इस चुनाव पर सिर्फ भारतीयों नहीं, पूरी दुनिया की नजर है। विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच राजनाथ सिंह ने कहा कि हम गुलाम कश्मीर पर अपना दावा कभी नही छोड़ेंगे। वैसे भी गुलाम कश्मीर के लोग हमारे ही लोग है, उन्हें पाकिस्तान ने कभी अपना माना ही नहीं है। राजनाथ सिंह का गुलाम कश्मीर के लोगों को संदेश पाकिस्तान के ताबूत में आखिरी कील की तरह है।

रक्षा मंत्री ने अपने वक्तव्य के जरिये चुनाव के परिदृश्यों को एक नया मोड़ दिया है। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस को भी निशाने पर लिया। उनके लिए ऐसा करना इसलिए आवश्यक हो गया था, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के नेता पाकिस्तानपरस्ती का परिचय देते हुए उससे बात करने पर जोर दे रहे हैं, लेकिन ऐसा करते हुए वे यह रेखांकित नहीं करते कि वार्ता के लिए उसे आतंकवाद पर लगाम लगानी होगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी कश्मीर के लोगों को अनुच्छेद-370 की वापसी का भी सपना दिखा रहे हैं। यह दिवास्वप्न के अलावा और कुछ नहीं, क्योंकि अब इस विभाजनकारी और अलगाववाद को बढ़ावा देने वाले अनुच्छेद की वापसी संभव नहीं और इसीलिए रामबन में राजनाथ सिंह ने कहा, भाजपा ने डंके की चोट पर अनुच्छेद 370 हटाकर जम्मू-कश्मीर में शांति और समृद्धि का रास्ता बनाया है। किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं कि वह इस अनुच्छेद को वापस ला सके। ऐसा कहते हुए उन्होंने कांग्रेस को भी निशाने पर लिया, जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है और अनुच्छेद-370 की वापसी के उसके वादे पर मौन धारण किए हुए है। पाकिस्तान एवं घाटी के विभिन्न राजनीतिक दल बार-बार अनुच्छेद 370 का जिक्र कर दुनिया के सामने यह गीत गाते रहे हैं कि 370 हटने से कश्मीर के लोग नाराज हैं। इस झूठ को खुलासा स्वयं कश्मीर की जनता ने लोकसभा चुनाव में वोटिंग के जरिये किया है।

घाटी में चुनाव में हिस्सेदारी कर रहे हैं राजनीतिक दल पाकिस्तानी राग अलापते रहे हैं। उमर अब्दुल्ला इस वक्त अफ़ज़ल को दी गयी फांसी के विवाद में घिर चुके हैं। उन्होंने कह दिया कि अफ़ज़ल को फाँसी देना गलत था। चूँकि अफ़ज़ल संसद पर हमले का ज़िम्मेदार था, उसकी तरफदारी करके नेशनल कान्फ्रेंस स्पष्ट रूप से जता रही है कि वह आतंकवादियों से मिली हुई है या उनकी तरफ़दारी कर रही है और कांग्रेस उसकी साथी है। इन स्थितियों में कांग्रेस को यह स्पष्ट करना चाहिए कि क्या वह नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणापत्र में किए गए वादों से सहमत है? उसे यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि क्या वह उमर अब्दुल्ला के इस आकलन से सहमत है कि संसद पर हमले की साजिश रचने वाले अफजल गुरु को फांसी की सजा देने से कुछ हासिल नहीं हुआ? यह अलगाववाद और आतंकवाद के दौर की वापसी के समर्थकों की हमदर्दी हासिल करने वाला ही बयान है और इसीलिए राजनाथ सिंह ने उन पर कटाक्ष किया कि अफजल को फांसी न दी जाती तो क्या उसके गले में हार डाले जाते। यह विडंबना ही है कि कांग्रेस उमर अब्दुल्ला के इस बयान पर भी चुप्पी साधे है, जबकि उसे फांसी की सजा मनमोहन सिंह सरकार के समय ही दी गई थी। ऐसे में कश्मीर के लोगों को तय करना होगा कि वे देश प्रेमियों के साथ हैं या देशद्रोहियों के साथ? बहरहाल, धारा 370 हटने के बाद यहाँ पहली बार हुए लोकसभा चुनाव में पचास प्रतिशत से ऊपर मतदान हुआ था जो अच्छा संकेत है। वर्ना इससे पहले तो तीस प्रतिशत मतदान को भी अच्छा समझा जाता रहा।

जम्मू एवं कश्मीर के चुनाव अनेक दृष्टियों से न केवल राजनीतिक दशा-दिशा स्पष्ट करेंगे बल्कि बल्कि राज्य के उद्योग, पर्यटन, रोजगार, व्यापार, रक्षा, शांति आदि नीतियों तथा राज्य की पूरी जीवन शैली व भाईचारे की संस्कृति को प्रभावित करेगा। वैसे तो हर चुनाव में वर्ग, जाति, सम्प्रदाय का आधार रहता है, पर इस बार वर्ग, जाति, धर्म, सम्प्रदाय व क्षेत्रीयता के साथ गुलाम कश्मीर एवं अनुच्छेद 370 के मुद्दे व्यापक रूप से उभर कर सामने आयेंगे। इन चुनावों में मतदाता जहां ज्यादा जागरूक दिखाई दे रहा है, वहीं राजनीतिज्ञ भी ज्यादा समझदार एवं चतुर बने हुए दिख रहे हैं। उन्होंने जिस प्रकार चुनावी शतरंज पर काले-सफेद मोहरें रखे हैं, उससे मतदाता भी उलझा हुआ है। अपने हित की पात्रता नहीं मिल रही है। कौन ले जाएगा राज्य की एक करोड पच्चीस लाख जनता को लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में विकास एवं शांति की दिशा में। इन स्थितियों में रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कश्मीर की जनता को जागरूक किया है एवं मतदान के प्रति सतर्क होने के साथ अपना मतदान विवेक से करने का वातावरण निर्मित किया है। (लेखक-ललित गर्ग/ ईएमएस)

मुफ्त की संस्कृति से पंजाब-हिमाचल की बढ़ी आर्थिक मुश्किलें

दिल्ली, पंजाब व हिमाचल सरकारों के सम्मुख वित्तीय संकट के धुंधलके छाने लगे हैं। सत्ता पर बैठी आम आदमी पार्टी एवं कांग्रेस की सरकारों के सामने चुनाव के दौरान वोटरों को लुभाने के लिए की गयी फ्रीबीज या रेवड़ी कल्चर की घोषणा आर्थिक संकट का बड़ा कारण बन रही है। मुफ्त की रेवड़ियां बांटने एवं लोक-लुभावन घोषणाओं के कितने भारी नुकसान होते हैं, इस बात को दिल्ली, पंजाब व हिमाचल सरकारों के सामने खड़ी हुई वित्तीय परेशानियों से समझा जा सकता है। इन सरकारों के लगातार बढ़ते राजस्व घाटा व बड़ी होती देनदारियां राज्य की अर्थव्यवस्था पर भारी पड़ रही हैं। विकास योजनाओं को तो छोड़े, इन राज्यों में कर्मचारियों को वेतन व सेवानिवृत्त कर्मियों को समय पर पेंशन देने में मुश्किलें आ रही हैं। इन जटिल होती स्थितियों को लेकर 'रेवड़ी कल्चर' पर न्यायालय से लेकर बुद्धिजीवियों एवं राजनीति क्षेत्रों में व्यापक चर्चा है। पंजाब के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग की हालिया रिपोर्ट में राज्य की वित्तीय प्राप्तियों और खर्चे के बीच बढ़ते राजकोषीय अंतर को उजागर किया गया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मुक्त की संस्कृति पर तीखे प्रहार करते हुए इसे देश के लिए नुकसानदायक परंपरा बता चुके हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने भी मुफ्त रेवड़ियां बांटने के चलन पर गंभीर चिंता जता चुके हैं। नीति आयोग के साथ रिजर्व बैंक भी मुफ्त की रेवड़ियों पर आपत्ति जता चुका है, लेकिन राजनीतिक दलों पर कोई असर नहीं है।

कैग की रिपोर्ट बताती है कि कैसे पंजाब राज्य का राजस्व घाटा, सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 1.99 फीसदी लक्ष्य के मुकाबले 3.87 फीसदी तक जा पहुंचा है। यह बेहद चिंताजनक स्थिति है कि राज्य का सार्वजनिक ऋण जीएसडीपी का 44.12 फीसदी हो गया है। यदि अब भी सत्ताधीश वित्तीय अनुशासन का पालन नहीं करते एवं मुक्त की सुविधाएं देने से बाज नहीं आते तो निश्चित ही राज्य को बड़ी मुश्किल की ओर धकेलने जैसी बात होगी। जिसका उदाहरण सामने है कि बीते माह का वेतन निर्धारित समय पर नहीं दिया जा सका है। इसके बावजूद सत्ता पर काबिज नेता मुफ्त की रेवड़ियों को बांटने का क्रम जारी रखे हुए हैं तो उसकी कीमत न केवल टैक्स देने वालों को चुकानी पड़ रही है बल्कि आम लोगों के जीवन पर भी इसका प्रतिकूल असर पड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर राज्य का खर्चा जहां 13 प्रतिशत की गति से बढ़ रहा है, वहीं राजस्व प्राप्तियां 10.76 फीसदी की दर से बढ़ रही हैं। जाहिर है, ये अंतर राज्य की आर्थिक बदहाली, आर्थिक असंतुलन एवं आर्थिक अनुशासनहीनता की तस्वीर ही उकेरता है। दिल्ली से लेकर पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकारें हों या हिमाचल प्रदेश से लेकर अन्य राज्यों में कांग्रेस की सरकारें तमाम तरह की मुफ्त की रेवड़ियां बांट कर भले ही वोट बैंक को अपने पक्ष में करने का स्वार्थी खेल खेला जा रहा हो, लेकिन इससे वित्तीय बजट लडखड़ाने ने इन राज्यों के लिये गंभीर चुनौती बन रहा हैं।

दरअसल, जिस भी नागरिक सुविधा को मुफ्त किया जाता है, उस विभाग का तो भट्टा बैठ जाता है। फिर उसका आर्थिक संतुलन कभी नहीं संभल पाता। कैग की हालिया रिपोर्ट बताती है कि पंजाब में एक निर्धारित यूनिट तक मुफ्त बिजली बांटे जाने से राज्य के अस्सी फीसदी घरेलू उपभोक्ता मुफ्त की बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं। ये और ऐसी ही अन्य मुफ्त सुविधाओं की भरमार के कारण सरकारों के सामने अपने कर्मियों को समय पर वेतन देने के लिये वित्तीय संकट है, जबकि वेतन पर आश्रित कर्मियों को राशन-पानी, बच्चों की स्कूल की फीस व लोन की ईएमआई आदि समय पर चुकाने में दिक्कत हो रही है। इन जटिल होते हालातों को देखते हुए अपेक्षा है कि राजनेता सस्ती लोकप्रियता पाने के लिये सब्सिडी की राजनीति एवं मुफ्त की संस्कृति से परहेज करें और वित्तीय अनुशासन से राज्य की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का प्रयास करें। जब भी ऐसी लोक-लुभावन घोषणाएं की जाती हैं तो उन दलों को अपने घोषणापत्र में यह बात स्पष्ट करनी चाहिए कि वे जो लोकलुभावनी योजना लाने जा रहे हैं, उसके वित्तीय स्रोत क्या होंगे? कैसे व कहां से यह धन जुटाया जाएगा? साथ ही जनता को भी सोचना चाहिए कि मुफ्त के लालच में दिया गया वोट कालांतर उनके हितों पर भारी पड़ेगा। जनता को गुमराह करते हुए, उन्हें ठगते हुए देश में रेवड़ियां बांटने का वादा और फिर उन पर जैसे-तैसे और अक्सर आधे-अधूरे ढंग से अमल का दौर चलता ही रहता है। लोकलुभावन वादों को पूरा करने की लागत अंततः मतदाताओं को खासकर करदाताओं को ही वहन करनी पड़ती है-अक्सर करों अथवा उपकरों के रूप में। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तेलंगाना विधानसभा चुनाव के समय मुफ्त रेवड़ियां देने के मुद्दे को उठाते हुए कहा था कि कई राज्यों ने अपनी वित्तीय स्थिति की अनदेखी करते हुए मुफ्त की सुविधाएं देने का वादा कर दिया है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी कुछ समय पहले उन दलों को आड़े हाथों लिया था, जो वोट लेने के लिए मुफ्त की रेवड़ियां देने के वादे करते हैं। उनका कहना था कि रेवड़ी बांटने वाले कभी विकास के कार्यों जैसे रोड, रेल नेटवर्क आदि का निर्माण नहीं करा सकते। वे अस्पताल, स्कूल और गरीबों के घर भी नहीं बनवा सकते। रेवड़ी संस्कृति अर्थव्यवस्था को कमजोर करने के साथ ही आने वाली पीढ़ियों के लिए घातक भी साबित होती है। इससे मुफ्तखोरी की संस्कृति जन्म लेती है। मुफ्त की सुविधाएं पाने वाले तमाम लोग अपनी आय बढ़ाने के जतन करना छोड़ देते हैं। पंजाब में महिलाओं को नगद राशि देने की घोषणा हुई, जबकि वहां की महिलाएं समृद्ध है। दिल्ली में उन महिलाओं को भी डीटीसी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा दी गई है, जिन्हें इस तरह की सुविधा की जरूरत नहीं। आधी आबादी को मुफ्त यात्रा की सुविधा देने से दिल्ली में डीटीसी को हर साल 15 करोड़ रुपये तक का नुकसान होगा। इस राशि का उपयोग दिल्ली के इन्फ्रास्ट्रक्चर पर किया जा सकता है। मुफ्तखोरी की राजनीति से देश का आर्थिक बजट लडखड़ाने का खतरा है। और इसके साथ निष्क्रियता एवं अकर्मण्यता को बल मिलेगा। हिंदुस्तान में लोगों को बहुत कम में जीवन निर्वहन करने की आदत है ऐसे में जब मुफ्त राशन, बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा मिलेगा तो काम क्यों करेंगे।

'गरीब की थाली में पुलाव आ गया है, लगता है शहर में चुनाव आ गया है' भारत की राजनीति से जुड़ी विसंगतियों एवं विडम्बनाओं पर ये दो पंक्तियां सटीक टिप्पणी हैं। चुनाव आते ही वोटरों को लुभाने के लिए जिस तरह राजनीतिक दल और उनके नेता वायदों की बरसात करते हैं, यह शासन-व्यवस्थाओं को गहन अंधेरों में धकेल देता है। मुफ्त की संस्कृति को कल्याणकारी योजना का नाम देकर राजनीतिक लाभ की रोटियां सेंकी जाती रही है। भारत जैसे विकासशील देश के लिये यह मुक्त संस्कृति एक अभिशाप बनती जा रही है। सच भी है कि मतदाताओं का एक बड़ा वर्ग आज भी इस स्थिति में है कि कथित तौर पर मुफ्त या सस्ती चीजें उसके वोट के फैसले को प्रभावित करती हैं। मुफ्त 'रेवड़ी' व कल्याणकारी योजनाओं में संतुलन कायम करना आवश्यक है, परंतु वोट खिसकने के डर से राजनीतिक दल इस बारे में मौन धारण किये रहते हैं, बल्कि न चाहते हुए भी इसे प्रोत्साहन भी देते हैं। फ्रीबीज' या मुफ्त उपहार न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में वोट बटोरने एवं राजनीतिक धरातल मजबूत करने का हथियार हैं। मुफ्त उपहार के मामले में कोई भी देश पीछे नहीं है। ब्रिटेन, इटली, जर्मनी, फ्रांस, डेनमार्क, स्वीडन, संयुक्त अरब अमीरात, बांग्लादेश, मलेशिया, कनाडा, अंगोला, कीनिया, कांगो, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया सहित अनेक देश इस दौड़ में शामिल हैं। विकसित देश जहां अपनी जीडीपी का 0.5 प्रतिशत से 1 प्रतिशत तक लोककल्याण योजनाओं में खर्च करते हैं, तो विकासशील देश जीडीपी का 3 प्रतिशत से 4 प्रतिशत तक फ्रीबीज के नाम पर खर्च कर देते हैं। भारत में अब जब न्यायालय की चौखट पर यह मुद्दा विचाराधीन है, तो संभावना है कि सरकार पर अनावश्यक आर्थिक भार डालने वाली घोषणाओं पर नियंत्रण को लेकर कोई राह भारत ही दुनिया को दिखाए। (लेखक-ललित गर्ग/ईएमएस)

संरक्षक पर प्रश्न चिन्ह- क्या अब भाजपा को संघ की जरूरत नही रही....?

भारत के मौजूदा सत्तारूढ़ खेमों में इस बात को लेकर अच्छी खासी चर्चा है कि ऐसी क्या खास वजह पैदा हो गई। जिससे देश पर राज कर रही भारतीय जनता पार्टी और उसके कथित संरक्षक संगठन राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आर.एस.एस.) के बीच अंदरूनी मनमुटाव की स्थिति पैदा हो गई और जिसके कारण भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को संघ की राष्ट्रीय समन्वयक बैठक में यह कहना पड़ कि- ''भाजपा को संघ की अब कोई जरूरत नहीं है, अब भाजपा हर तरीके से अपने आपमें सक्षम और आत्मनिर्भर है।'' भाजपाध्यक्ष के इस बयान की देश के राजनीतिक क्षेत्रों में अच्छी खासी चर्चा है और कथन को लेकर मौजूदा और भविष्य के कयासों पर अटकलें तेज है। भाजपाध्यक्ष के इस बयान से संघ स्वयं वाली विस्मित है तथा अब वह अपनी अगली रणनीति को लेकर सजग व सक्रिय हो गया है, संघ प्रमुख केरल के पलक्कड में सम्पन्न इस सम्मेलन के बाद काफी चिंतित और सक्रिय हो गए है, उन्होंने पिछले कुछ दिनों में अपने विश्वस्तों के साथ कई बार गंभीर मंत्रणाएं भी की है।

अब भाजपाध्यक्ष जगतप्रकाश नड्ड़ा के इस तल्खी भरे बयन के राजनीतिक क्षेत्रों में कई अर्थ निकाले जा रहे है, संघ इस बात को लेकर चिंतित है कि प्रधानमंत्री की मौन स्वीकृति के बिना नड्ड़ा जी ऐसा बयान दे नही सकते और मोदी जी की संघ के प्रति यह मुद्रा क्यों है? यह किसी के भी समझ में नही आ रहा है। भाजपाध्यक्ष ने यह बयान संघ के करीब दस दिन पहले केरल के पलक्कड़ शहर में हुए सम्मेलन में दिया था, बयान तिथि से अब तक के दस दिन के समय में भाजपाध्यक्ष के इस बयान की काफी राजनीतिक सर्जरी हो चुकी है और वह अभी भी जारी है, इस कारण भाजपा और संघ दोनों में ही खलबली मची हुई है।

अब ऐसे मौके पर राजनीतिक प्रेक्षकों को मोदी का राजनीतिक इतिहास याद आ रहा है, जब मोदी के गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए दंगों के बाद अटल जी का सार्वजनिक रूप से मोदी से की गई तल्खी भरी बातचीत और मोदी की दो टूक सफाई इसके साथ ही मुख्यमंत्री के रूप में मोदी के इस समय हुए दिल्ली दौरों और अटल-अड़वानी की तत्कालीन राजनीतिक भूमिका व मोदी के प्रति बर्ताव भी इन दिनों राजनीतिक क्षेत्रों में समीक्षा का विषय बना हुआ है और आज प्रधानमंत्री की संघ के प्रति तल्खी को उसी संदर्भ में जांचा परखा जो निकलेगें वे सार्वजनिक हो पाएगें या नही? यह तो फिलहाल कहना मुश्किल है, किंतु यह सही है कि इन परिणामों की प्रतीक्षा सभी को है, संघ को भी और मोदी खेमें को भी।

हाँ, तो चर्चा का मुख्य विषय संघ की मौजूदा स्थिति, उसका भाजपा पर असर और दोनों की भावी रणनीति है, अब यहां मौजूदा स्थिति को देखकर यह कहना भी गलत नही होगा कि मोदी और उनकी टोली को संघ की कोई चिंता नही है और यही संघ की चिंता का भी मुख्य कारण है और भाजपाध्यक्ष के स्पष्ट बयान ने तो स्थिति को और भी साफ कर दिया है, अब यदि संघ को अपने आपका अस्तित्व कायम रखना है तो उसे बिना किसी से सहयोग की अपेक्षा रखे खुद को ही इस दिशा में प्रयास करना पड़ेगें और अब यह भी स्पष्ट हो चुका है कि संघ को मोदी से किसी भी प्रकार के सहयोग या आदर भाव की अपेक्षा भी करना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि सत्ता के गुरूर में डूबी भाजपा व उसके नेता कई बार संघ को इसी तरह के संकेत दे चुके है, इसलिए अपनी अस्मिता कायम रखने के लिए संघ को ही प्रयास जारी रखना होगें, उसकी मद्द के लिए कोई साथ नही आएगा। अब इस सामयिक चेतावनी को संघ समय रहते समझ ले तो ठीक है, वर्ना मोदी का तो अभी करीब-करीब पूरा ही तीसरा कार्यकाल बाकी है। (लेखक-ओमप्रकाश मेहता/ ईएमएस)

शब्द पहेली - 8125

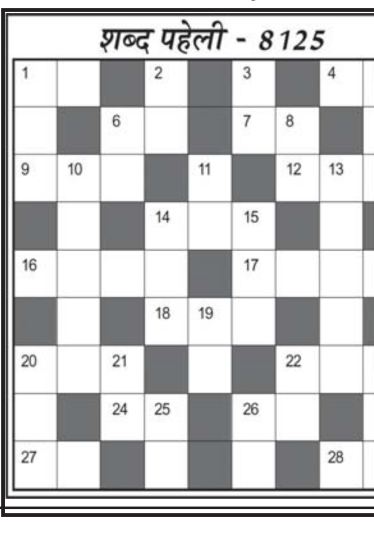

बाएँ से दाएँ

1.निशा,रात (उर्दू-2)
4.ताला (अंग्रेजी-2)
6.दुलारा,लाडला-2
7.बढ़ावा,समर्थन-2
9.निवास,घर,नीड़-3
12.कमी-3
14.पनाह,आश्रय-3
16.अंगूठे से तीसरी अंगुली, सावित्री-4
17.सज्जनता,सभ्यता-4
18.गिरवी रखी वस्तु-3
20.एक राशि-3
22.दबाव (अंग्रेजी-3)
24.कुल,मुनाफा-2
26.उम्मीद,आशा-2
27.मादा का विलोम-2
28.आगमन-2

ऊपर से नीचे

1.मदिरा,मय-3
2.ऐश्वर्या व अक्षय खन्ना की फिल्म-2
3.सम्मान,प्रसिद्धि-2
5.डोली उठाने वाले-3
6.वेस्टइंडीज की क्रिकेट टीम के कप्तान-2
8.अधिकार-2
10.सेनापति,कप्तान-2,3
11.पति की मां-2
13.आत्मबलिदानी -5
14.कद काठी-3
15.रसद,किराणा-3
19.प्रत्येक-2
20.मैला,अस्वच्छ-3
21.मिट्टी,धूल-2
22.छापाखाना-2
23.जिव्हा,जीभ-3
25.सम्मान-2
26.फलों का राजा-2

शब्द पहेली -8124 का हल

Jagrutidaur.com, Bangalore

खेल - समाचार

आखिर कौन हैं.......जिसने दुनिया में कर दी भारत की किरकिरी

नई दिल्ली (ईएमएस)। क्रिकेट इतिहास में इससे अजीब स्थिति कभी दिखाई नहीं दी। दो टीमें हैं जो मैच खेलना चाहती हैं। दोनों टीमों के सभी खिलाड़ी मैदान पर हैं। अंपायर और मैच रेफरी भी मौजूद हैं। बारिश नहीं, धूप खिली हुई है। लेकिन खेल नहीं हो सकता क्योंकि दो दिन पहले हुई बारिश के चलते मैदान गीला है। और यह सब उस देश में हो रहा है, जो क्रिकेट का सुपरपावर है। जिस देश का क्रिकेट बोर्ड अपनी अमीरी के लिए जाना जाता है।

हम बात कर रहे हैं अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड टेस्ट मैच की, जो ग्रेटर नोएडा के शहीद विजय सिंह पथिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में होना है। टेस्ट मैच होने के चलते पूरी दुनिया की निगाह इस पर है। पूरी दुनिया में भारत का मजाक बन रहा है, क्योंकि जिस मैच को 9 को शुरू होना था, वह 10 दिसंबर को भी दोपहर 3 बजे तक शुरू नहीं हुआ है। अफगानिस्तान क्रिकेट अधिकारी कह रहे हैं कि उनसे गलती हुई। अब वे यहां दोबारा कभी नहीं आएंगे। लेकिन सबसे अमीर बोर्ड बीसीसीआई खामोश है। बोर्ड के किसी भी पदाधिकारी का इस पर कोई बयान नहीं दिया है। जबकि हर कोई जानता है कि बिना बीसीसीआई की इजाजत के भारत में आधिकारिक क्रिकेट मैच नहीं हो सकता। अगर अफगानिस्तान ने भारत को अपना 'होम' चुना है, तब इसमें बीसीसीआई और आईसीसी की सहमति है। जिस मैच में बीसीसीआई की सहमति हो, उसका यह हश्र होगा, यह बात हजम नहीं होती।

ऐसा नहीं है कि बीसीसीआई के पास संसाधनों की कमी है। ग्रेटर नोएडा के जिस स्टेडियम में अफगानिस्तान-न्यूजीलैंड टेस्ट मैच होना है, उससे चंद किलोमीटर दूर दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली प्रीमियर लीग हुई। तकरीबन तीन हफ्ते चली इस लीग में बारिश के कुछ देर बाद ही मैच आसानी से कराए गए। तब क्या अफगानिस्तान-न्यूजीलैंड टेस्ट मैच के लिए किसी इसतरह के स्टेडियम को मेजबानी नहीं दी जानी चाहिए थी, जहां पर्याप्त संसाधन हों।

यह सही है कि अफगानिस्तान ने 2015 से 2017 के बीच बतौर होस्ट ग्रेटर नोएडा में कई मैच खेल चुकी हैं। लेकिन क्या बीसीसीआई और आईसीसी को यह सुनिश्चित नहीं करना चाहिए था कि टेस्ट मैच के लिए या तो कोई दूसरा बेहतर वेन्यू चुना जाता या फिर ग्रेटर नोएडा के मौजूदा स्टेडियम में अच्छी सुविधाएं मुहैया कराई जातीं। यह बड़ा सवाल है कि जिस स्टेडियम को बीसीसीआई ने कुछ साल पहले बैन किया था, वहीं पर टेस्ट मैच क्यों करवाया गया।

बात दें कि 2017 में बीसीसीआई ने विजय सिंह पथिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को बैन कर दिया था। वजह थी इस मैदान पर तब एक प्राइवेट लीग खेली गई थी, जिसे बोर्ड से मान्यता हासिल नहीं थी। जाहिर है इस मैदान के कर्ताधर्ताओं की पहली प्रायरिटी इंटरनेशनल मैचों के इतर भी कुछ रही होगी। नहीं ऐसा क्यों होता कि जिस स्टेडियम में इंटरनेशनल मैच हो रहे हों, वह ऐसी प्राइवेट लीग की मेजबानी करता, जिसके कारण मैदान को बैन झेलना पड़े। लेकिन अब यह मामला ग्रेटर नोएडा के स्टेडियम का नहीं रह गया है। यह पूरे देश का सवाल है।

सच कहूं.....अभी डिकॉक को लेकर मुझे कोई जानकारी नहीं,मुख्य कोच रॉब वॉल्टर ने कहा

जोहांसबर्ग (ईएमएस)। दक्षिण अफ्रीका के मुख्य कोच रॉब वॉल्टर ने कहा है कि उन्हें विकेटकीपर-बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक के टी20 इंटरनेशनल भविष्य के बार में कोई स्पष्टता नहीं है। उन्हें अबू धाबी में आयरलैंड के खिलाफ होने वाली दो मैचों की टी20 सीरीज के लिए नहीं चुना गया है। डिकॉक पहले ही टेस्ट और वनडे क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं। वे वेस्टइंडीज के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज से भी बाहर थे और आयरलैंड के खिलाफ भी नहीं खेल रहे है। वॉल्टर ने कहा, सच कहूं तब मुझे नहीं पता। फिलहाल क्विंटन और मेरे बीच इस बात को लेकर कोई चर्चा नहीं हो रही है कि वे फिर से द.अफ्रीका के लिए खेलना चाहते हैं या नहीं। मैंने उनके लिए दरवाजा खुला रखा है, अगर वह चाहे मुझसे संपर्क कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि ऐसा कभी न हो। डिकॉक ने 2021 में टेस्ट क्रिकेट से और फिर वनडे वर्ल्ड कप के बाद वनडे से संन्यास लिया था। हालांकि, उन्होंने टी20 वर्ल्ड कप में खेलने का फैसला किया था, जो अमेरिका और वेस्टइंडीज में हुआ था। उस टूर्नामेंट में वह दक्षिण अफ्रीका के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे और उनकी टीम फाइनल तक पहुंची थी।

उसके बाद डिकॉक ने मेजर लीग क्रिकेट और कैरेबियन प्रीमियर लीग में हिस्सा लिया और अब वह एसए20 और आईपीएल में भी खेलते रह सकते है। लेकिन वॉल्टर ने साफ किया कि उनकी टीम में जगह पक्की नहीं है और यह उनके प्रदर्शन पर निर्भर करेगी। वॉल्टर ने कहा, हो सकता है कि हम कभी बातचीत करें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होगा कि वह टीम में चयनित हो जाएंगे। अब सबसे ज्यादा जरूरी चीज प्रदर्शन होगा। वह अभी इतने बूढ़े नहीं हुए हैं कि प्रदर्शन के आधार पर उनकी वापसी की बात न हो।

डिकॉक के अंतिम निर्णय के लिए वॉल्टर ने कोई समय सीमा तय नहीं की है। उनकी अनुपस्थिति में दक्षिण अफ्रीका रीजा हेंड्रिक्स को ओपनर के तौर पर आजमा रही है। उनके पास काइल वेरेनी, रयान रिकेलटन और हेनरिक क्लासेन जैसे विकेटकीपिंग विकल्प भी हैं। इनमें से सिर्फ क्लासेन आगामी अफगानिस्तान और आयरलैंड के खिलाफ सीरीज के लिए टीम का हिस्सा नहीं हैं।

ऐसा क्या हुआ, मैच खेलते-खेलते सभी खिलाड़ी व अंपायर जमीन पर लेट गए

नई दिल्ली,(ईएमएस)। क्रिकेट मैच में कई बार बड़े रोमांचक दृश्य देखने को मिलते हैं जो एक यादगार बन जाते हैं। क्रिकेट मैच के दौरान कभी सांप तो कभी कुत्ता मैदान में आ जाता है। रणजी ट्रॉफी के मुकाबले के दौरान मधुमक्खियों ने मैदान पर मौजूद खिलाड़ियों पर हमला कर दिया। इस दौरान सभी खिलाड़ी जमीन पर लेट गए और उन्होंने अपना बचाव किया था। किसी को भी इस हमले में कोई नुकसान नहीं हुआ।

दरअसल यह बात है 2023 में यूपी और उड़ीसा का मैच चल रहा था। दूसरे दिन लंच ब्रेक के बाद जब यूपी टीम की बल्लेबाजी कर रही थी तभी मधुमक्खियों ने खिलाड़ियों पर हमला कर दिया। मैदान पर मौजूद सभी खिलाड़ी और अंपायर अपनी जान बचाने जमीन पर लेट गए। कई मिनट तक मधुमक्खियों का झुंड मैदान पर मंडराता रहा इसके बाद वह वहां से दूर चला गया फिर सभी खिलाड़ी समेत अंपायर खड़े हो गए और मैच को दोबारा शुरू हुआ। बता दें कि यह घटना भामाशाह पार्क में हुई थी जो कि मेरठ में स्थित है।

ऐसा पहली बार नहीं था। जब खिलाड़ियों पर मधुमक्खियों ने हमला किया हो। आईसीसी वर्ल्ड कप 2009 में दक्षिण अफ्रीका और श्रीलंका के बीच खेले गए मैच में भी मधुमक्खियां में आ गई थीं। 1979 में भारत के मुकाबले में भी मधुमक्खियों ने आतंक मचाया था। इसके अलावा 2000 में रणजी ट्रॉफी मैच में भी मधुमक्खियों ने मैदान में बाधा डाली थी। 2019 के वर्ल्ड कप में दक्षिण अफ्रीका और श्रीलंका के मैच में मधुमक्खियों ने हमला कर दिया था। श्रीलंका की पारी के 48वें ओवर में अचानक से सभी खिलाड़ी और अंपायर मैदान पर लेट गए। सुरंगा लकमल और इसुरु उडाणा उस समय क्रीज पर थे। यह देखकर दर्शक और कमेंटेटर्स हैरान रह गए। उन्होंने समझ नहीं आ रहा था कि मैदान पर ऐसा क्या हुआ कि सभी खिलाड़ी और अंपाचल जमीन पर लेट गए बाद में पता चला कि मधुमक्खियों ने हमला कर दिया था।

मैदान की हालत देख अफगानिस्तान टीम ने दोबारा यहां ना आने की खाई कसम

दिल्ली के नोएडा स्टेडियम में होना था अफगान-न्यूजीलैंड का टेस्ट मैच

नई दिल्ली,(ईएमएस)। अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड टेस्ट मैच में ऐसी स्थिति पैदा हो गई है, जो पहले कभी देखने को नहीं मिली। दोनों टीमों के बीच भारत में खेला जाने वाला टेस्ट मैच दूसरे दिन भी शुरू नहीं हो सका। दोनों टीमें पूरी तरह तैयार हैं लेकिन मौसम इसमें अडंगा डाल रहा है। नोएडा स्टेडियम की खराब तैयारी ने पूरा मैच खराब कर दिया है। टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में इससे खराब स्थिति कभी देखी ही नहीं गई जब दो दिन से बारिश नहीं हुई हो और इसके बावजूद मैदान गीला होने के चलते खेल नहीं हो पा रहा है। अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच 9 सितंबर से टेस्ट मैच खेला जाने वाला था। यह मैच ग्रेटर नोएडा के शहीद विजय सिंह पथिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में होना है। दोनों टीमें नोएडा पहुंच चुकी हैं लेकिन खेल नहीं पा रही हैं। दरअसल, मैच शुरू होने के एक दिन पहले यहां बारिश हुई। रात में बूंदाबांदी होती रही लेकिन सोमवार को मैच शुरू होना था, उस दिन बारिश नहीं हुई। कुछ समय बादल जरूर छाए और धूप भी निकली लेकिन स्टेडियम की गीली आउटफील्ड और घटिया जल निकासी के चलते पहले दिन का खेल बिना एक भी गेंद फेंके रद्द करना पड़ा।

एसए20 क्रिकेट लीग के लिए एक अक्टूबर को होगी नीलामी : स्मिथ

डरबन (ईएमएस)। दक्षिण अफ्रीका की एसए20 लीग के कमिश्नर ग्रीम स्मिथ ने कहा है कि तीसरे सत्र के लिए खिलाड़ियों की नीलामी एक अक्टूबर को होगी। स्मिथ ने कहा कि इस नीलामी में 13 खिलाड़ियों को शामिल किया जाएगा। एसए20 लीग का तीसरा सत्र 9 जनवरी से 8 फरवरी 2025 के बीच होगा। सत्र से पहले खिलाड़ियों को बरकरार रखने और टीमों को 13 और खिलाड़ियों के चयन का अवसर मिलेगा।

इस लीग में दक्षिण अफ्रीका सहित दुनिया भर के खिलाड़ी खेलेंगे। भारत के दिनेश कार्तिक भी इस लीग में पार्ल रॉयल्स टीम से खेलेंगे। वह इस लीग में खेलने वाले पहले भारतीय होंगे। इस लीग में हर टीम को तीसरे सत्र के लिए नया खिलाड़ी शामिल करना होगा जबकि तीन टीमों को 30 दिसंबर से पहले वाइल्ड कार्ड की घोषणा करनी होगी। कार्तिक के अलावा इंग्लैंड के बेन स्टोक्स, न्यूजीलैंड के केन विलियमसन, इंग्लैंड के जो रूट, न्यूजीलैंड के ट्रेंट बोल्ट, और इंग्लैंड के जॉनी बेयरस्टो, न्यूजीलजैंड के डेवोन कोंवे, जाक क्राउली के अलावा अफगानिस्तान के राशिद खान और रहमानुल्लाह गुरबाज भी इस लीग में खेलेंगे।

आईटी और फार्मा ने दौड़ाया बाजार लगातार दूसरे दिन हरे निशान पर बंद

मुंबई (ईएमएस)। मंगलवार को एशियाई बाजारों में मिलेजुले रुख के बीच भारतीय शेयर बाजार में लगातार दूसरेदिन तेजी दर्ज हुई और दोनों प्रमुख इंडेक्स बढ़त के साथ बंद हुए। अमेरिका के महंगाई के आंकड़े जारी होने से पहले आईटी शेयरों में तेजी और कैंसर की चुनिंदा दवाओं पर जीएसटी घटने पर फार्मा शेयरों में लिवाली के चलते बाजार चढ़कर बंद हुआ।

30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स मंगलवार को तेजी के साथ 81,768.72 अंक पर खुला और कारोबार के दौरान 82,196.55 अंक के उच्च स्तर तक चला गया था। अंत में सेंसेक्स 0.44 प्रतिशत या 361.75 अंक की बढ़त लेकर 81,921.29 पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी-50 भी मंगलवार को सकारात्मक नोट के साथ खुला। इंट्रा-डे ट्रेड के दौरान 25,130.50 अंक के हाई लेवल तक जाने के बाद अंत में निफ्टी 104.70 अंक की तेजी के साथ 25,041.10 पर बंद हुआ।

सेंसेक्स की कंपनियों में एनटीपीसी का शेयर सबसे ज्यादा 2.41 प्रतिशत की तेजी आई। साथ ही एचसीएल टेक, भारती एयरटेल, टेक महिंद्रा, पावर ग्रिड, एक्सिस बैंक, टीसीएस, अदाणी पोर्ट्स, टाइटन, मारुति और इंफोसिस के शेयर प्रमुख रूप से लाभ में रहे। वहीं दूसरी तरफ, बजाज फिनसर्व का शेयर सबसे ज्यादा 1.77 प्रतिशत गिरकर बंद हुआ। इसके अलावा बजाज फाइनेंस, हिंदुस्तान यूनिलीवर, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर्स, एसबीआई के शेयर भी गिरकर बंद हुए।

दरअसल अमेरिकी शेयर बाजार में सोमवार को आए उछाल का असर भारतीय शेयर बाजार पर भी पड़ा। साथ ही विदेशी और घरेलू निवेशकों की लिवाली तथा क्रूड आयल की कीमतों में कमी के चलते बाजार चढ़कर बंद हुआ।

एशियाई बाजारों में मंगलवार को मिलाजुला रुख देखने को मिला। चीन और हांगकांग का स्टॉक मार्किट जहां बढ़त में बंद हुए। वहीं दक्षिण कोरिया का कॉपी और जापान का निक्केई 225 गिरावट में बंद हुआ। इसके अलावा यूरोपीय बाजार मंगलवार को मिलेजुले रुख के साथ कारोबार कर रहे थे जबकि अमेरिकी शेयर बाजार सोमवार को उछाल के साथ बंद हुए।

सोना-चांदी के भाव में गिरावट

- सोने के वायदा भाव 71,600, चांदी 83,600 रुपए के करीब

नई ?दिल्ली (ईएमएस)। सोने के वायदा भाव मंगलवार को तेजी के साथ खुलने के बाद नरम पड़ गए, जबकि चांदी के वायदा कारोबार की शुरुआत गिरावट के साथ ही हुई। मंगलवार को सोने के वायदा भाव 71,600 रुपये के करीब, जबकि चांदी के वायदा भाव 83,600 रुपये के करीब कारोबार कर रहे थे। वै?श्विक बाजार में सोने-चांदी के वायदा भाव की शुरुआत तेजी के साथ हुई।सोने के वायदा भाव की शुरुआत आज तेजी के साथ हुई। लेकिन बाद में इसके भाव में गिरावट देखी जाने लगी। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर सोने का बेंचमार्क अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट आज 67 रुपये की तेजी के साथ 71,695 रुपये के भाव पर खुला। इस समय यह 17 रुपये की गिरावट के साथ 71,611 रुपये के भाव पर कारोबार कर रहा था। चांदी के वायदा भाव की शुरुआत आज सुस्त रही। एमसीएक्स पर चांदी का बेंचमार्क दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट 4 रुपये की गिरावट के साथ 83,641 रुपये पर खुला। इस समय यह 37 रुपये की गिरावट के साथ 83,608 रुपये के भाव पर कारोबार कर रहा था। वै?श्विक बाजार में सोने-चांदी के वायदा भाव की शुरुआत तेजी के साथ हुई। लेकिन बाद में दोनों के भाव सुस्त पड़ गए। कॉमेक्स पर सोना 2,536 डॉलर प्रति औंस के भाव पर खुला। पिछला बंद भाव 2,532.70 डॉलर प्रति औंस था। इस समय यह 0.70 डॉलर की नरमी के साथ 2,532 डॉलर प्रति औंस के भाव पर कारोबार कर रहा था। कॉमेक्स पर चांदी के वायदा भाव 28.69 डॉलर के भाव पर खुले, पिछला बंद भाव 28.65 डॉलर था। इस समय यह 0.02 डॉलर की गिरावट के साथ 28.63 डॉलर प्रति औंस के भाव पर कारोबार कर रहा था।

सेबी ने इंफोसिस को दी राहत, 16 इकाइयों और पूर्व कर्मचारियों से रोक हटाई

मुंबई (ईएमएस)। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने इन्फोसिस के शेयरों में इनसाइडर ट्रेडिंग से जुड़े मामले में कंपनी के कुछ पूर्व कर्मचारियों समेत 16 इकाइयों और व्यक्तियों पर लगे प्रतिबंध हटा दिए। यह मामला जुलाई 2020 में तब सामने आया था जब इन्फोसिस के शेयरों में संभावित इनसाइडर ट्रेडिंग का अलर्ट मिला था। यह अलर्ट तब आया जब कंपनी ने 30 जून, 2020 को खत्म हुई तिमाही के नतीजे जारी किए थे। सेबी ने जांच की कि क्या कुछ इंडिविजुअल ने अनपब्लिश्ड प्राइस-सेंसिटिव इन्फार्मेशन का उपयोग करके इंफोसिस के शेयरों का कारोबार किया, जो कि इनसाइडर ट्रेडिंग नियमों का उल्लंघन है। सेबी ने इन्फोसिस भेदिया कारोबार मामले में 16 इकाइयों पर लगे प्रतिबंध हटा दिए हैं, जिनमें कुछ पूर्व कर्मचारी भी शामिल हैं। सेबी ने यह भी निर्देश दिया कि अमित भूतरा, भरत सी जैन, कैपिटल वन पार्टनर्स, टेसोरा कैपिटल, मनीष सी जैन और अंकुश भूतरा पर अंतरिम आदेश के तहत लगाए गए प्रतिबंध भी तत्काल प्रभाव से खत्म किए जाएं।

सेबी के पूर्णकालिक सदस्य अश्विनी भाटिया ने 57 पन्नों के अपने अंतिम आदेश में कहा कि नोटिसधारकों के खिलाफ अंतरिम आदेश और पुष्टिकरण आदेश को रद्द करना और सभी नोटिसधारकों के खिलाफ कार्रवाई का निपटारा करना उचित है। उन्होंने यह भी बताया कि सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल ने 25 अप्रैल, 2022 को दिए अपने आदेश के जरिए पहले ही अंतरिम और पुष्टिकरण आदेश को रद्द कर दिया था।

यह मामला तब सामने आया जब सेबी ने दिसंबर 2019 से सितंबर 2020 तक इन्फोसिस के वित्तीय नतीजों की घोषणाओं के दौरान संदिग्ध ट्रेडिंग गतिविधियों की पहचान की। सेबी ने जांच की कि क्या कुछ व्यक्तियों ने इन्फोसिस के अनपब्लिश्ड प्राइस-सेंसिटिव इनफार्मेशन का इस्तेमाल करके कंपनी के शेयरों का कारोबार किया, जो कि इनसाइडर ट्रेडिंग नियमों का उल्लंघन है। मार्केट रेगुलेटर ने पाया कि 8 व्यक्तियों ने इन नियमों का उल्लंघन किया और 2021 में उनके खिलाफ एक अंतरिम आदेश जारी किया। हालांकि, दो व्यक्तियों ने इस आदेश को सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल में चुनौती दी, जिसे खारिज कर दिया गया था।

चीन का निर्यात 8.7 प्रतिशत बढ़कर 308.65 अरब डॉलर हुआ

हांगकांग (ईएमएस)। ?विदेशों में मांग बढ़ने की वजह से चीन के निर्यात में लगातार पांचवें महीने वृद्धि दर्ज की गई। हालांकि धीमी होती चीनी अर्थव्यवस्था के बीच आयात में गिरावट आई है। चीन के सीमा शुल्क कार्यालय द्वारा मंगलवार को जारी आंकड़ों के अनुसार अगस्त में निर्यात पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 8.7 प्रतिशत बढ़कर 308.65 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया। यह अर्थशास्त्रियों के करीब 6.5 प्रतिशत के अनुमान से अधिक है। जुलाई में निर्यात सात प्रतिशत की दर से बढ़ा था। अगस्त में यह आंकड़ा 18 महीने में सबसे मजबूत है। इसकी बड़ी वजह अगस्त 2023 में कम आधार है, जब निर्यात में 8.8 प्रतिशत की गिरावट आई थी। तुलनात्मक रूप से एक साल पहले की तुलना में आयात में केवल 0.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई। यह अर्थशास्त्रियों द्वारा लगाए गए करीब दो प्रतिशत के अनुमान से कम है। कैपिटल इकोनॉमिक्स के जिचुन हुआंग ने कहा ?कि निर्यात मूल्य पिछले 17 महीने में सबसे तेज गति से बढ़े हैं। निर्यात की मात्रा रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई है। हमें उम्मीद है कि निकट भविष्य में निर्यात मजबूत रहेगा, जिसे चीन की वास्तविक प्रभावी विनिमय दर में गिरावट से समर्थन मिल रहा है। चीन का व्यापार अधिशेष अगस्त में बढ़कर 91.02 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया, जो जुलाई में 84.65 अरब अमेरिकी डॉलर था। निर्यात की मांग बढ़ रही है, लेकिन चीन घरेलू मांग को बढ़ाने के लिए संघर्ष कर रहा है। सोमवार को जारी आंकड़ों के अनुसार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक अगस्त में 0.6 प्रतिशत बढ़ा, जो पूर्वानुमानों से कम है। अधिकारियों ने खराब मौसम के कारण खाद्य कीमतों में वृद्धि को उच्च सीपीआई का कारण बताया। हालांकि मुख्य सीपीआई अगस्त में केवल 0.3 प्रतिशत बढ़ा, जो तीन वर्षों में सबसे कम है। फैक्टरी प्रबंधकों के एक आधिकारिक सर्वेक्षण के अनुसार अगस्त में चीन की विनिर्माण गतिविधि छह महीने के निचले स्तर पर आ गई, पिछले सप्ताह जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार क्रय प्रबंधक सूचकांक 49.1 पर आ गया। 50 से नीचे का आंकड़ा विनिर्माण गतिविधि में संकुचन को दर्शाता है।

जीवन बीमा कंपनियों का नया कारोबार प्रीमियम 22 फीसदी बढ़ा

नई दिल्ली (ईएमएस)। जीवन बीमा कंपनियों की अगस्त में नई पॉलिसी की बिक्री से प्रीमियम आय 22 प्रतिशत बढ़कर 32,644 करोड़ रुपए हो गई। उद्योग निकाय जीवन बीमा परिषद की तरफ से जारी मासिक आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2024-25 के पहले 5 महीनों में बीमा कंपनियों का नया कारोबार प्रीमियम संग्रह 21 प्रतिशत बढ़कर 1,54,194 करोड़ रुपए हो गया जबकि पिछले साल की समान अवधि में यह 1,27,661 करोड़ रुपए था। इन आंकड़ों से पता चलता है कि नए पॉलिसी से प्रीमियम आय बढ़कर अगस्त में 32,644 करोड़ रुपए हो गई जबकि अगस्त, 2023 में यह 26,788.55 करोड़ रुपए थी। इस साल अब तक का प्रीमियम संग्रह पिछलेसाल के1,27,661 करोड़ रुपए से बढ़कर1,54,194 करोड़ रुपए हो गया। व्यक्तिगत उपभोक्ताओं और कॉरपोरेटग्राहकोंकी ओर से बीमा सुरक्षा की मांग लगातार बने रहने के बावजूद अगस्त, 2024 में नई पॉलिसी जारी करने की संख्या 1.44 प्रतिशत घटकर 23,94,007 रह गई। पिछले साल की समान अवधि में बीमा कंपनियों ने 24,28,895 पॉलिसी बेची थीं। जीवन बीमा कंपनियों ने पिछले महीने 1,08,147 व्यक्तिगत जीवन बीमा एजैंट को जोड़ा। वित्त वर्ष 2024-25 की शुरुआत में मौजूद एजैंटों की कुल संख्या 3.74ल बढ़ चुकी है।

दुनिया में सबसे अधिक रोजगार देने वाला देश भारत

मुंबई (ईएमएस)। कैलेंडर वर्ष 2024 की चौथी तिमाही में वैश्विक स्तर पर भारतीय कॉरपोरेट जगत में नियुक्ति की धारणा मजबूत है। कंपनियां देश की आर्थिक स्थिति को लेकर उत्साहित हैं। इसके बाद 37 प्रतिशत नियोक्ता अपने कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने की योजना बना रहे हैं।

एक सर्वेक्षण में यह बात सामने आई।

रोजगार परिदृश्य सर्वेक्षण 2024 चौथी तिमाही के अनुसार, भारत में शुद्ध रोजगार परिदृश्य 37 प्रतिशत के साथ दुनिया भर में सबसे मजबूत है। भारत के बाद कोस्टा रिका 36 प्रतिशत और अमेरिका 34 प्रतिशत के साथ क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। शुद्ध रोजगार परिदृश्य (एनईओ) की गणना कर्मचारियों की संख्या में कटौती की आशंका रखने वाले नियोक्ताओं के प्रतिशत से नियोक्ताओं को काम पर रखने की मंशा रखने वाले नियोक्तओं के प्रतिशत को घटाकर की जाती है। चौथी तिमाही (अक्टूबर-दिसंबर) के लिए भारत का रोजगार परिदृश्य 37 प्रतिशत रहा, जो तीसरी तिमाही से सात प्रतिशत अधिक है।

पिछले वर्ष की सामना अवधि की तुलना में यह अपरिवर्तित है।

सर्वेक्षण के अनुसार भारत का उत्तरी क्षेत्र 41 प्रतिशत की संभावना के साथ नौकरी की मांग में सबसे अधिक है। इसके बाद 39 प्रतिशत के साथ पश्चिमी क्षेत्र का स्थान है। भारत, सिंगापुर और चीन में रोजगार परिदृश्य मजबूत बना है। हांगकांग में नियोक्ता रोजगार को लेकर सबसे अधिक सतर्क रहे। सर्वेक्षण एक से 31 जुलाई 2024 के बीच मिले के जवाबों पर आधारित है। कंपनियां देश की आर्थिक स्थिति को लेकर उत्साहित हैं। इसमें 42 देशों के 40,340 नियोक्ताओं से उनकी चौथी तिमाही की नियुक्ति संबंधी मंशा के बारे में सवाल किया गया था।

पुतिन ने नाटो में डाली फूट......यूक्रेन के खिलाफ जंग लड़ रहे सदस्य देश के नागरिक

मास्को (ईएमएस)। 925 दिनों की भीषण जंग के बाद अब रूस यूक्रेन के युद्ध में कुछ ऐसा हुआ है कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और यूक्रेन हैरान हैं। यकीन करना मुश्किल हो रहा है, लेकिन नाटो के 32 देश में से एक ऐसा देश है जिसके लड़ाके पुतिन की तरफ से यूक्रेन पर भयंकर हमले कर रहे हैं। इस खबर के सामने आते ही पूरा नाटो सदमे में चला गया है। रूस यूक्रेन जंग को लेकर बहुत बड़ा खुलासा नाटो देश ने किया है। पहली बार किसी नाटो देश ने स्वीकार किया है कि उसके देश के लड़के रुस की तरफ से यूक्रेन पर हमला कर रहे हैं। इस खुलासे के बाद से नाटो की इमरजेंसी मीटिंग होने वाली है। इधर पुतिन ने फिर से साबित कर दिया है कि रूस ही जंग का असली उस्ताद है।

नाटो देश और अमेरिका कोई यह समझ नहीं पा रहा कि उसके लड़ाके पुतिन के वफादार कैसे हो गए। शुरू में कुछ जानकारों को शक था कि शायद नाटो देश तुर्की के लड़ाके रूस की तरफ से यूक्रेन पर हमला कर रहे हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि यूक्रेन पर हमले कर रहे उसके पड़ोसी मुल्क लिथुआनिया के लोग है। यानी यूक्रेन के रक्षक की उसके लिए भक्षक बन चुके हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति की खुद को युद्ध का चाणक्य समझ रहे थे। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड खुद को युद्ध का गेम चेंजर समझ रहे थे। लेकिन पुतिन ने लगभग तीन साल के जंग में ऐसी बाजी पलटी है कि चर्चा यह तेज हो चली है कि पुतिन का रूस यूक्रेन के कीव तक कब्जा करने जा रहा है।

नाटो के लड़ाके रुस की ओर से लड़ रहे हैं इसका दवा लिथुआनिया की तरफ से किया गया है। लिथुआनिया के रक्षा मंत्री लॉरीनाम कमीयुनाम ने कहा कि इस वक्त लिथुआनिया के सैकड़ो लड़ाके रूस की तरफ से यूक्रेन पर हमले कर रहे हैं। उनका दावा है कि उनके देश के नागरिक रूस की तरफ से जंग लड़ रहे हैं। लिथुआनिया के रक्षा मंत्री ने कहा है कि रूस की तरफ से लड़ने वाले लिथुआनियाई नागरिकों को सख्त सजा मिलेगी।

हमास-इजराइल युद्ध रुकवाने भारत की तरफ देख रही दुनिया

जीसीसी बैठक में जयशंकर बोले-गाजा के हालात हमारी सबसे बड़ी चिंता

रियाद,(ईएमएस)। रूस और यूक्रेन युद्ध खत्म के लिए दुनियाभर के देश भारत की और उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को पीएम मोदी का संदेश देने मास्को गए हैं। वहीं हमास-इजराइल जंग खत्म करवाने के लिए भारत की मध्यस्थता की मांग उठती रही है। इस बीच रियाद में हुई जीसीसी बैठक में भारत ने इस जंग को लेकर साफ कहा कि गाजा पट्टी में इजराइल और हमास के बीच पिछले कई महीनों से जंग जारी है। इस लड़ाई में करीब 40 हजार फलस्तीनी आम नागरिक मारे गए हैं।

इसे लेकर जयशंकर ने सऊदी अरब की राजधानी रियाद में मुस्लिम देशों के नेताओं के साथ बैठक में कहा कि गाजा के मौजूदा हालात अब हमारी सबसे बड़ी चिंता है। इस संबंध में भारत का रुख सैद्धांतिक और एक समान रहा है। हम आतंकवाद जैसी घटनाओं की निंदा करते हैं, लेकिन बेगुनाह नागरिकों पर हुई बमबारी से लगातार हो रही मौतों से हमें गहरा दुख है। जयशंकर ने कहा कि किसी भी कार्रवाई में मानवीय कानून के सिद्धांतों को ध्यान में रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम जल्द से जल्द जंग रोकने का समर्थन करते हैं।

जयशंकर ने कहा कि भारत दो-राष्ट्र समाधान के जरिये फिलिस्तीन के मसले के समाधान के लिए खड़ा है। उन्होंने कहा कि भारत ने फलस्तीनी संस्थानों और क्षमताओं के निर्माण में भी योगदान दिया है। विदेश मंत्री ने कहा कि जहां तक मानवीय स्थिति का सवाल है, हमने राहत प्रदान की है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी को अपना सहयोग बढ़ाया है। जीसीसी एक प्रभावशाली समूह है, जिसमें संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, बहरीन, ओमान, कतर और कुवैत जैसे देश शामिल हैं। वित्त वर्ष 2022-23 में जीसीसी देशों के साथ भारत का कुल व्यापार 184.46 अरब अमेरिकी डॉलर रहा था।

जीसीसी बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गाजा में मौजूदा स्थिति को भारत की सबसे बड़ी चिंता बताया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भारत इस क्षेत्र में जल्द से जल्द जंग खत्म कराने का समर्थन करता है। उन्होंने कहा कि रणनीतिक वार्ता के लिए पहली भारत-जीसीसी मंत्रिस्तरीय बैठक में भाग लेना उनके लिए बहुत खुशी की बात है। उन्होंने कहा कि यह बैठक न केवल उपलब्धियों पर विचार करने का अवसर है, बल्कि भविष्य के लिए एक महत्वाकांक्षी और दूरगामी मार्ग तैयार करने का अवसर भी है। उन्होंने कहा कि हमारे लोगों के बीच संबंध हमारे रिश्तों की नींव हैं। करीब 90 लाख भारतीय यहां रहते हैं, जो हमारे बीच एक जीवंत सेतु का काम करते हैं। हम उनके कल्याण और सुविधा देने के लिए आपको शुक्रिया अदा करते हैं।

बांग्लादेश की अंतरिम सरकार रोहिंग्या शरणार्थियों को करेगी देश से बाहर

-2017 में म्यांमार से भागकर बांग्लादेश आ गए थे

ढाका,(ईएमएस)। बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार लगातार शेख हसीना सरकार के फैसलों को खत्म यानी पलट रही है। अब यूनुस सरकार उन रोहिंग्या शरणार्थियों को देश से बाहर करने जा रही है, जिन्हें कभी शेख हसीना ने पनाह दी थी। अपने देश में रहने का मौका दिया था। अमेरिका इस मामले में उनकी मदद का ऐलान कर चुका है। बांग्लादेश में पहले से ही 10 लाख से ज्यादा रोहिंग्या शरणार्थी रह रहे हैं। 2017 में जब म्यांमार की सेना ने कार्रवाई की तो ये सभी म्यांमार से भागकर बांग्लादेश आ गए थे। इनमें से ज्यादातर मुसलमान हैं। बांग्लादेश में तब शेख हसीना की सरकार थी। पहले तो उन्होंने इन्हें वापस लेने के लिए बांग्लादेश पर दबाव बनाया। यहां तक कि इन परिवारों को म्यांमार वापस जाने के लिए दो हजार डॉलर आर्थिक मदद देने का ऐलान भी किया, लेकिन तब कोई भी रोहिंग्या वापस नहीं गया। बांग्लादेश और म्यांमार के बीच साल 2017 में हुए समझौते के तहत शरणार्थियों को म्यांमार वापस जाना था लेकिन कोई कामयाबी नहीं मिली। इसके बाद शेख हसीना ने कई बाद कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पाई। आखिरकार उन्होंने इन रोहिंग्या को कई जिलों में बाडे बनाकर बसा दिया। इन्हें खाने-पीने का सामान मुहैया कराया लेकिन शेख हसीना के सत्ता से बेदखल होने के बाद अस्थिरता का फायदा उठाते हुए तमाम रोहिंग्या फिर बांग्लादेश में घुसने लगे। इससे यूनुस सरकार की चिंता बढ़ गई है। अब इन्हें बाहर करने के लिए सरकार ने योजना तैयार की है। मोहम्मद यूनुस ने हाईलेवल बैठक की, जिसमें रोहिंग्याओं जल्द से जल्द किसी तीसरे देश में बसाने पर मंथन किया गया। इस बैठक में इंटरनेशनल ऑर्गनाइजेशन फॉर माइग्रेशन के अधिकारी भी शामिल हुए। इन लोगों को अमेरिका समेत कई विकसित देशों में बसाया जा सकता हैं। अमेरिका पहले ही हजारों रोहिंग्याओं को अपने यहां शरण देने का ऐलान कर चुका है लेकिन इस प्रक्रिया में तेजी लाई जानी चाहिए।

युनूस ने कहा इनका माइग्रेशन लगातार होना चाहिए। शरण देने वाले देशों के साथ बात की जानी चाहिए। बांग्लादेश से माइग्रेशन 12 साल बाद फिर शुरू होने जा रहा है। उम्मीद है कि इसमें सफल होंगे। बांग्लादेश के कॉक्स बाजार में ये बांग्लादेशी रहते हैं। इसे दुनिया का सबसे बड़ा रिफ्यूजी कैंप भी कहा जाता है। करीब पांच लाख रोहिंग्या रखाइन प्रांत में बनाए गए शिविरों में रहते हैं।

सुपर टाइफून के कारण 8 लाख से अधिक घर प्रभावित,-चीन में तबाही का मंजर

बीजिंग (ईएमएस)। 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चीन से टकराया सुपर टाइफून यागी को 2024 का सबसे ताकतवर तूफान घोषित किया गया है। यागी से टूरिस्टों के बीच पॉपुलर चीन के हवाई आईलैंड में जनजीवन ही ठप पड़ गया। इस तूफान के कारण 8 लाख 30 हजार से अधिक घर प्रभावित हुए हैं।

इस तूफान की वजह से 2 लोगों की मौत हो गई है जबकि 92 लोग घायल हुए हैंचीन के दक्षिणी प्रांत और आसपास के इलाकों में ऐसा कहर बरपाया है कि स्कूल, समुद्री तट पर होटल्स, बिजनेस, फ्लाइट और बोट सर्विस सब बंद करनी पड़ गई।'यागी' तूफान इस साल हैनान में आया 11वां तूफान है। शुक्रवार स्थानीय समयानुसार दोपहर 4 बजकर करीब 20 मिनट पर हैनान प्रांत के वेंगतियान शहर के पास समुद्री तट से टकराया।इस समय इसकी रफ्तार 234 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक थी।इसी हफ्ते की शुरुआत में यागी ने उत्तरी फिलीपींस किया था. इसने खूब तबाही मचाई। इसकी वजह से तूफान के साथ जमकर बारिश हुई। इसमें कम से कम 16 लोगों की मौत भी हुई। चारों ओर सिर्फ तबाही का मंजर दिख रहा था। लोग रस्सी से घरों पर गिरे पेड़ को हटाते हुए दिख रहे थे। चारों तरफ सिर्फ कीचड़-ही-कीचड़ दिख रहे थे।

जानकारी के अनुसार यागी के हिट करते ही हैनान में बिजली गुल हो गई। इससे प्रांत के 8 लाख 30 हजार घर प्रभावित हुए। बिजली आपूर्ति विभाग ने 7 हजार सदस्यों वाली एक आपातकालीन टीम गठित की है, जो परिस्थितियां अनुकूल होते ही मरम्मत कार्य शुरू कर देगी। वहीं, शुक्रवार की रात को 2 लाख 60 हजार घरों की बिजली बहाल कर दी है। यागी के आगमन के बाद से मानो हैनान का पूरा जनजीवन ठप पड़ गया हो। वहीं, टाइफून के आने के अलर्ट जारी होने के समुद्र तटों और भव्य होटलों के लिए प्रसिद्ध इस आइलैंड की फ्लाइट्स और बोट, स्टीमर और यॉट सर्विस बंद करनी पड़ गई। 1 करोड़ से अधिक आबादी वाला शहर लॉकडाउन हो चुका था। हैनान में यागी के टकराने के बाद मंजर काफी भयावह था। सड़कों और घरों पर पेड़ गिरे हुए दिखे।

जलभराव के बाद आपात टीम लोगों को रेस्क्यू कर रही थी। कमर तक पानी लगे हुए थे। सुपर टाइफून यागी के कारण हांगकांग, मकाऊ और ग्वांगडोंग प्रांत में स्कूल, बिजनेस और ट्रांसपोर्ट पहले ही बंद हो चुके थे। साथ ही वियतनाम में हवाई अड्डे को भी बंद कर दिया गया था। चीन के मौसम विभाग का अनुमान है कि यागी वीकेंड में लाओस के साथ-साथ वियतनाम को हीट करेगा। तूफान के कारण स्थिति खराब हो सकती है। हांगकांग में गुरुवार को 50 फ्लाइट्स रद्द होने के बाद शुक्रवार को फिर से परिचालन शुरू कर दिया है। वहीं, यागी वियतनाम की ओर बढ़ गया है।

अडानी को कोर्ट ने दिया झटका, केन्या सरकार से हुई डील पर लगाई रोक

नैरोबी,(ईएमएस)। एशिया के अमीर लोगों में शामिल गौतम अडानी ने केन्या सरकार के साथ 1.85 अरब डॉलर का समझौता था लेकिन केन्या की हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। इस डील से अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड को केन्या की राजधानी नैरोबी के जोमो केन्याटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को 30 साल तक ऑपरेट करने का अधिकार मिल जाता। यह केन्या का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है लेकिन कोर्ट के अगले आदेश तक इस डील के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी गई है।

एक रिपोर्ट के मुताबिक नैरोबी में जोमो केन्याटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को अडानी एयरपोर्ट को लीज पर देने के केन्या सरकार के फैसले को कोर्ट में चुनौती दी गई है। केन्या ह्यूमन राइट्स कमीशन के साथ-साथ वकीलों की संस्था ने भी इस कदम को असंवैधानिक बताया है। उन्होंने याचिका में कहा है कि स्ट्रैटजिक और प्रॉफिट कमा रहे इस एयरपोर्ट को किसी भारत की निजी कंपनी को लीज पर देने का तुक नहीं है। यह सुशासन, जवाबदेही, पारदर्शिता और पब्लिक मनी के विवेकपूर्ण और जिम्मेदार उपयोग के संवैधानिक सिद्धांतों का उल्लंघन है। केन्या सरकार ने डील का बचाव करते हुए कहा है कि एयरपोर्ट की मौजूदा कैपेसिटी से संबंधी समस्याओं में तत्काल सुधार की जरूरत है।

अडानी एंटरप्राइजेज ने अपनी अबू धाबी स्थित अपनी सहायक कंपनी ग्लोबल एयरपोर्ट्स ऑपरेटर के जरिए से एयरपोर्ट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर की स्थापना की है। अडानी की कंपनी ने केन्या सरकारको2029 तक एक नए टर्मिनल और टैक्सीवे सिस्टम के लिए 750 मिलियन के निवेश का प्रस्ताव दिया है।साथही2035 तक एयरपोर्ट में सुधार के लिए अतिरिक्त 92 मिलियन का निवेश करने की तैयारी है। अगर यह डील होती है तो यह भारत के बाहर अडानी ग्रुप का पहला एयरपोर्ट होगा। अभी यह ग्रुप देश में आधा दर्जन से ज्यादा एयरपोर्ट्स का संचालन कर रहा है।

मोटर वाहन उद्योग का जीएसटी में 14-15 प्रतिशत योगदानः सियाम

नई दिल्ली (ईएमएस)। भारतीय मोटर वाहन उद्योग ने वित्त वर्ष 2023-24 में 20 लाख करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया और अब देश में संग्रहित कुल जीएसटी में इसका योगदान 14-15 प्रतिशत है।' सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स' (सियाम) के एक अ?धिकारी ने सोमवार को यहां 64वें वार्षिक एसीएमए सत्र में कहा कि मोटर वाहन क्षेत्र देश में प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। भारतीय मोटर वाहन उद्योग ने वित्त वर्ष 2023-24 में 20 लाख करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया, हम देश में एकत्र कुल माल एवं सेवा कर (जीएसटी) में करीब 14-15 प्रतिशत का योगदान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि मोटर वाहन उद्योग देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 6.8 प्रतिशत के मौजूदा स्तर से अधिक योगदान देगा। उन्होंन कहा ?कि अग्रवाल ने कहा कि केवल वृद्धि संख्या ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि प्रौद्योगिकी में बदलाव भी उतना ही महत्वपूर्ण है।

दो साल में मंगल ग्रह पर लांच किया जाएगा पहला स्टारशिप मिशनः मस्क

सैन फ्रांसिस्को (ईएमएस)। टेस्ला और स्पेसएक्स के सीईओ एलन मस्क ने कहा कि मंगल ग्रह पर पहला अनक्रूड स्टारशिप मिशन दो साल में लांच ??किया जा सकता है। स्टारशिप दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट है। इसका उपयोग इंसानों को चंद्रमा और फिर अंत में मंगल ग्रह पर भेजने के लिए किया जाएगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में टेक अरबपति ने कहा ?कि मंगल ग्रह पर पहला स्टारशिप दो साल में लॉन्च होगा।

चीन ने चंद्रमा की मिट्टी से बनाई ईंट,तीन साल तक चांद पर परखेगा,फिर बनाएगा घर

बीजिंग(ईएमएस)। चीन ने चंद्रमा की क्रत्रिम मिट्टी से एक ईंट तैयार की है। इस ईंट को तीन साल के लिए चांद पर छोड़ा जाएगा। परीक्षणों पर ईंट खरी उतरती है तो घर बनाने की शुरुआत की जाएगी। रिपोर्ट के अनुसार, वुहान स्थित हुआझोंग विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के साइंटिस्ट डिंग लियुन और उनकी टीम वर्षों से इन ईंटों पर काम कर रही थी। डिंग ने बताया कि इन ईंटों को अगले महीने तियानझोउ-8 कार्गो स्पेसक्रॉफ्ट से तियानगोंग स्पेस स्टेशन भेजा जाएगा। हम तीन साल तक इन ईंटों पर नजर रखेंगे और देखेंगे कि इन पर रेडिएशन और टेंपरेचर का कितना असर होता है। क्या ये ईंटें खराब होती हैं या नहीं।

चांद जैसा वातावरण बनाने के लिए वैज्ञानिकों ने मिट्टी को ग्रेफाइट के सांचे में ढाला। फिर इन्हें पकाने के लिए वैक्यूम हॉट प्रेस भट्ठी में रखा। इससे ये ईंटें पत्थरों से भी ज्यादा कठोर हो गई हैं। चीन 2035 तक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक रिसर्च सेंटर बनाना चाहता है, इसे इंटरनेशनल लूनर रिसर्च स्टेशन नाम दिया जाएगा। अप्रैल तक 10 से ज्यादा देश चीन के इस मुहिम में शामिल हो चुके हैं। डिंग के मुताबिक, यह अंडे के आकार का होगा। इसे रोबोट की मदद से चांद की मिट्टी का इस्तेमाल कर वहां घर बनाया जाए। दूसरा विकल्प ये है कि रोबोट वहां की ईंटें इकट्ठा करे, उसे पारंपरिक तरीके से पकाए। हमें उम्मीद है कि रियल चंद्र मिट्टी से बनी पहली ईंट 2028 में बनाई जाएगी। डिंग ने एक लाइव शो में कहा, हम धरती पर ईंटों को 100 मेगापास्कल की ताकत तक पका सकते हैं, जो कंक्रीट से कहीं अधिक कठोर है। लेकिन क्या ये ईंटें चांद जैसे कठोर वातावरण का सामना कर पाएंगी, ये हमें देखना होगा। हमने हूबहू चांद की मिट्टी की तरह धरती पर एक मिट्टी तैयार की है।

चीन में लिपिस्टिक के विज्ञापन को लेकर मच गया हंगामा

बीजिंग (ईएमएस)। चीन में एक कॉस्मेटिक ब्रांड के लिप ग्लॉस स्टिक विज्ञापन पर विवाद खड़ा हो गया है। आलोचक विज्ञापन को वल्गर कह रहे हैं। विज्ञापन में एक मॉडल को दिखाया गया है जो लिप ग्लॉस को लगाते हुए दिखती हैं। इसकी आलोचना करने वाले कह रहे हैं कि ये विज्ञापन बेशर्मी और अश्लीलता की हद है क्योंकि इस लिप ग्लॉस का शेप पुरुष जननांग की तरह है। उनका कहना है कि ये कैसी संस्कृति को परोसा जा रहा है और विज्ञापन के नाम पर ये किस तरह की अश्लीलता को परोसा जा रहा है।

ये विवाद तब शुरू हुआ जब दो सितंबर को बिनी ग्लास नाम के चर्चित ब्लॉगर ने इसके बारे में आवाज बुलंद की। इस ब्लॉगर के 50 लाख फॉलोअर्स हैं। इस ऐड के प्रमोशन, डिजाइन और ब्रांड के तौर-तरीकों पर सवाल खड़े करते हुए लिखा कि कंपनी ने जानबूझकर अपने प्रोडक्ट को लोकप्रिय बनाने के लिए इस फूहड तरीके को चुना है। ये विज्ञापन महिलाओं की गरिमा के खिलाफ है और उनको अपमानजनक तरीके से पेश करता है।

विज्ञापन ऐसा लगता है कि कंपनी की मार्केटिंग रणनीति पुरुषों के अंग कंसेप्ट पर आधारित है। यानी एक महिला को इस तरह से पुरुष को आनंद देने के लिए सेक्सुअल ऑब्जेक्ट के रूप में पेश किया जा रहा है। ये सरासर अपमानजनक है। महिलाओं का तिरस्कार करने वाला है और जहां वे एक तरफ खुद के अधिकारों के प्रति जागरूक हो रही हैं वैसे माहौल में ये विज्ञापन महिलाओं के प्रति संकीर्ण सोच को दिखाता है। इसके साथ ही उन्होंने जोड़ा कि जहां एक तरफ महिलाएं कंज्यूमर के रूप में अपनी प्राथमिकताएं खुद तय कर रही हैं वही दूसरी ओर इस तरह का कुत्सित प्रयास उनको प्रोडक्ट के रूप में पेश करता है।

सिर्फ इतना ही नहीं कंपनी को लिप कलर्स के नाम रखने पर भी तीखे विरोध का सामना करना पड़ रहा है। मसलन आलोचना करने वाले कह रहे हैं कि गर्ल्स के लिए एक लिप कलर प्रोडक्ट का नाम किस लिटिल जूजू है। जूजू का चीनी भाषा में कोई अर्थ नहीं है। यानी ये जूजू क्या है? सोशल मीडिया यूजर्स कह रहे हैं कि कौन इस तरह की लिपिस्टिक खरीदेगा। अगर किसी ने पूछा कि आपकी लिपिस्टिक का शेड क्या है तब कोई कैसे ये कह सकेगा कि इसका नाम किस लिटिल जूजू है? ऐसा लगता है कि ये किसी लिपिस्टिक का नहीं बल्कि सेक्स टॉय का विज्ञापन है।

विदाई की आहट- जस्टिन ट्रूडो से पार्टी के नाराज सांसद मांग रहे इस्तीफा

टोरंटो (ईएमएस)। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो से उन्ही की पार्टी के नेता खुश नहीं हैं। वे खुलकर ट्रूडो का विरोध कर रहे हैं और इस्तीफा मांग रहे हैं। ट्रूडो सरकार पर साथी एनडीपी के साथ छोड़ने के बाद से ही संकट के बादल मंडरा रहे हैं। मंगलवार को पार्टी के सांसदों के साथ उनकी अहम बैठक शुरू होने जा रही है। हालांकि पार्टी के अंदर से भी ट्रूडो को निराशा ही हाथ लग रही है। लिबरल पार्टी के सांसद अलेजांदार मेंडेस ने बताया कि पार्टी के अंदर भी यही स्वर उठ रहे हैं कि अब प्रधानमंत्री की विदाई होनी चाहिए। उन्होंने प्रधानमंत्री के तौर पर ट्रूडो की तारफी भी की। वह रेडियो कनाडा पर बात कर रही थीं। उन्होंने कहा, मैंने यह एक या दो लोगों से नहीं बल्कि दर्जनों लोगों से सुना है कि अब आगे के लिए जस्टिन ट्रूडो सही नेता नहीं हैं। ऐसे में उन्हें विदा ले लेनी चाहिए।

ब्रिटिश कोलंबिया में आयोजित कॉकस की बैठक में बैंक ऑफ इंग्लैंड के पूर्व गवरनर मार्क कारनी को आर्थिक मामलों का विशेष सलाहकार बनाने का भी औपचारिक ऐलान किया जा सकता है। सोमवार को जारी बयान में ट्रूडो नेकहा, देश की अर्थव्यवस्था को आगेबढ़ाने के लिए मार्क के पास बड़ा विजनहै। वह मध्य वर्ग को मजबूत करनाचाहते हैं। कनाडा में सर्वे भी यही बता रहे हैं कि फिलहाल कंजरवेटिव पार्टी लिबरलसे15 से20 पॉइंट से आगे निकल रही है। ऐसे में अगले चुनाव में भी लिबरल पार्टी की हार की गुंजाइश दिख रही है। चुनाव से पहले जस्टिन ट्रूडो का हटना वैसे भी तय माना जा रहा था। इससे पहले ब्रूनस्विक के सांसद वायने लॉन्ग ने भी अगले आम चुनाव से पहले जस्टिन ट्रूडो को इस्तीफा देने की सलाह दी थी। कनाडा में अब अक्टूबर 2025 में आम चुनाव होने हैं। हालांकि उससे पहले ही जस्टिन ट्रूडो की सरकार गिरने की आशंका बनी हुई है। अगर उनकी सरकार गिर जाती है तो मध्यावधि चुनाव कराए जा सकते हैं। न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी (एनडीपी) ने सप्लाई ऐंड कॉन्फिडेंस अग्रीमेंट अपनी तरफ से रद्द करते हुए ट्रूडो की पार्टी से गठबंधन थोड़ लिया था। मार्च 2022में दोनों पार्टियों में गठबंधन हुआथा।कनाडाके हाउस ऑफ कॉमन्स में कुल 338 सीटें हैं। लिबरल पार्टी के पास 154 सांसद हैं। वहीं एनडीपी की समर्थन वापसी के पास सरकार अल्पमत में आ गई है।

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 'गुजरात राज्य इंस्टीटयूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन- ग्रिट' का गठन

- प्रधानमंत्री के 'विकसित भारतॅ2047' के संकल्प को साकार करने की दिशा में गुजरात का एक विशिष्ट कदम

गांधीनगर (ईएमएस)ॅमुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में गुजरात ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 'विकसित भारतॅ2047' के संकल्प को 'विकसित गुजरातॅ2047' के जरिए साकार के लिए एक विशिष्ट कदम उठाया है। नीति आयोग की तर्ज पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता में 'गुजरात राज्य इंस्टीटयूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन- ग्रिट' का गठन किया गया है। राज्य सरकार ने विकसित भारतॅ2047 के लिए विकसित गुजरात के ध्येय मंत्र के साथ मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के मार्गदर्शन में 'विकसित गुजरातॅ2047' का एक डायनेमिक विजन डॉक्यूमेंट- रोडमैप तैयार किया है। इस विजन डॉक्यूमेंट में दर्शाये गए दीर्घकालिक और अल्पकालिक लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए रणनीतिक योजनाएं बनाने के लिए 'ग्रिट' एक थिंक टैंक के रूप में मार्गदर्शन और नेतृत्व प्रदान करेगा। मुख्यमंत्री 'ग्रिट' की गवर्निंग बॉडी के अध्यक्ष होंगे, जबकि उपाध्यक्ष के रूप में वित्त मंत्री और सदस्य के रूप में कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा और उद्योग विभाग के मंत्रियों का समावेश किया गया है। इसके अलावा, गवर्निंग बॉडी के अन्य सदस्यों में मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार, मुख्य सचिव, वित्त एवं योजना विभाग के अपर मुख्य सचिव या प्रधान सचिव, कृषि, वित्त और आर्थिक मामले, औद्योगिक ढांचागत सुविधाओं और स्वास्थ्य तथा पोषण, कौशल वर्धन, रोजगार और शिक्षा आदि क्षेत्रों के राज्य सरकार द्वारा नामित विशेषज्ञ रहेंगे। 'ग्रिट' की इस गवर्निंग बॉडी के सदस्य सचिव के रूप में सेवानिवृत्त या सेवारत अपर मुख्य सचिव स्तर का अधिकारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) होगा। इस सीईओ की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाएगी।

गुजरात राज्य इंस्टीटयूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन (ग्रिट) के कार्यक्षेत्र में निम्नांकित मामलों और विषयों का समावेश किया गया है उनमेः पांच ट्रिलियन यूएस डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए टास्क फोर्स कमेटी द्वारा की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन की समीक्षा करना। उद्योग, कृषि, निवेश और निर्यात जैसे क्षेत्रों के विकास से लेकर राज्य के संतुलित आर्थिक विकास की वृद्धि पर देखरेख रखते हुए सिफारिशें करना। राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्र मों की समीक्षा, मूल्यांकन, सुपरविजन और 'विकसित गुजरातॅ2047' डॉक्यूमेंट के दीर्घकालिक विजन के अनुरूप आवश्यक सिफारिशें करने के साथ ही सुधार के क्षेत्रों को प्राथमिकता देना। राज्य के विजन डॉक्यूमेंट की प्राथमिकताओं के सुसंगत नीति निर्माण करना और निर्णय लेने के लिए सुशासन को प्रोत्साहन देना। दीर्घकालिक सर्वग्राही विकास के लिए थ्रस्ट एरिया (जोर दिए जाने वाले या महत्वपूर्ण क्षेत्र) की सिफारिश करना। राज्य सरकार के विभागों, भारत सरकार, नीति आयोग तथा नागरिक समाज एवं अन्य हितधारकों के बीच समन्वय को प्रोत्साहित कर विकास के लिए नए कदमों का सुझाव देना। राज्य के बहुआयामी विकास के लिए सिफारिशें करना तथा राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सफल नीतियों और श्रेष्ठ प्रथाओं की समीक्षा करना। क्रॉस-सेक्टोरल पार्टनरशिप, डोमेन नॉलेज सपोर्ट और कैपिटल बिल्डिंग कार्यक्रमों के लिए अग्रणी संस्थानों का सहयोग लेना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, रोबोटिक्स, जीआईएस, ड्रोन टेक्नोलॉजी और ब्लॉकचेन जैसे इनोवेटिव कार्यक्रमों और टेक्नोलॉजी को प्रोत्साहित करना। राज्य सरकार को एसेट्स मोनेटाइजेशन, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीटयूशन, सीएसआर, ट्रस्ट फंड्स और अन्य स्रोतों द्वारा राज्य के विकास के लिए वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए मैकेनिज्म विकसित करने की सिफारिशें देना।

'ग्रिट' के इस कार्यक्षेत्र के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए गवर्निंग बॉडी और रोजमर्रा के कामकाज के लिए एक्जीक्यूटिव कमेटी का गठन किया जाएगा। गवर्निंग बॉडी के सुझावों और 'ग्रिट' के निर्णयों के क्रियान्वयन तथा रोजमर्रा के कामकाज के लिए 10 सदस्यीय एक्जीक्यूटिव कमेटी काम करेगी। इस कमेटी के चेयरमैन के रूप में 'ग्रिट' के सीईओ, जबकि संयोजक के रूप में सामान्य प्रशासन विभाग के आयोजन प्रभाग के सचिव होंगे। 'ग्रिट' की गवर्निंग बॉडी की बैठक साल में कम से कम एक बार और जब कभी गवर्निंग बॉडी के चेयरमैन को इसकी आवश्यकता हो, तब आयोजित की जाएगी। वहीं, एक्जीक्यूटिव कमेटी की बैठक साल के दौरान हर तीन महीने में आयोजित करनी होगी। 'ग्रिट' के गठन और उसके कार्यक्षेत्र से संबंधित विधिवत प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभाग- आयोजन प्रभाग द्वारा जारी किया जाएगा।

एएमसी में कांग्रेस की गुटबाजी का आखिरकार राज खुल गयाः शहजाद खान पठान विपक्ष के नेता बने रहेंगे...

अहमदाबाद (ईएमएस)अहमदाबाद नगर निगम में विपक्ष के नेता को बदलने का विवाद एक बार फिर बिगड़ गया है. आज कांग्रेस कार्यालय में हुई बैठक में शहजाद खान पठान को एएमसी में विपक्ष के नेता पद पर बरकरार रखने का फैसला लिया गया है. एएमसी में विपक्ष के नेता की कुर्सी को लेकर कांग्रेस में गुटबाजी का भूत खत्म हो गया था, लेकिन आज की बैठक के अंत में सभी सानेपत ने बैठकर शहजाद खान पठान को पद पर बने रहने की मंजूरी दे दी है.

अहमदाबाद में कांग्रेस में एक बार फिर सांप्रदायिकता का भूत दिखा और नगर निगम में विपक्ष के नेता को बदलने की मांग उठी. इसके आधार पर आज पालडी स्थित कांग्रेस कार्यालय में नए विपक्षी नेता की चयन प्रक्रिया आयोजित की गई। कुल 23 नगरसेवकों में से दानिलिम्दा नगरसेवक शहजाद खान 15 पठान समर्थक नगरसेवक थे। आमची में विपक्ष के नेता के नाम को लेकर घमासान छिड़ गया है. अंत में शहजाद खान ने सभी समझौते करके पठान को वहीं रहने की इजाजत दे दी है.

वर्तमान में अहमदाबाद मु. निगम में विपक्ष के नेता शहजाद खान पठान हैं और अहमदाबाद शहर अध्यक्ष नीरव बख्शी का समूह उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहा था। पूरे विवाद को लेकर आज कांग्रेस कार्यालय में शहर कांग्रेस अध्यक्ष हिम्मत सिंह पटेल और पूर्व राज्यसभा सांसद अमीबेन याग्निक की मौजूदगी में चुनाव हुआ.

गुजरात में यातायात समस्या के त्वरित निपटारे के लिए राज्य सरकार की नई पहल

अहमदाबाद (ईएमएस)ॅराज्य में यातायात की समस्या को हल करने के लिए गुजरात सरकार ने एक नई पहल की है। राज्य में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं और ट्रैफिक जाम से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए गुजरात पुलिस द्वारा नागरिकों के लिए एक विशेष हेल्पलाइन-18002331122 सेवा शुरू की गई है। इस नई हेल्पलाइन पर नागरिक एक फोन कॉल से राज्य के किसी भी कोने में सड़क दुर्घटना, ट्रैफिक जाम की समस्या या यातायात संबंधी किसी अन्य समस्या की सूचना दे सकेंगे। यह सूचना तत्काल संबंधित क्षेत्र के पुलिस पदाधिकारी को देकर समस्या का समाधान कराया जायेगाॅयातायात संबंधी इस हेल्पलाइन के अलावा गुजरात पुलिस ने नागरिकों के लिए तीन अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराई हैं। जिसमें नागरिकों की सुविधा के लिए स्मार्टफोन उपयोगकर्ताओं के लिए वेबसाइट, ईमेल आईडी और विशेष एप्लिकेशन की सेवा शामिल की गई है। 180023 31 122 हेल्पलाइन पर कॉल आने पर संबंधित जिला पुलिस अधिकारी को समस्या के समाधान के लिए तत्काल कार्रवाई करनेका निर्देश दिया जाएगा। एप्लीकेशन में एक खास फीचर सिटीजन फर्स्ट जोड़ा गया है, जिससे ट्रैफिक जाम या सड़क दुर्घटना से जुड़ी कोई भी शिकायत स्मार्ट फोन के जरिए एप्लीकेशन के जरिए की जा सकेगीॅइस एप्लीकेशन के माध्यम से कोई भी व्यक्ति मोबाइल से फोटो खींचकर पुलिस को समस्या बता सकता है। जिसकी लोकेशन के आधार पर पुलिस रियल टाइम मॉनिटरिंग कर इस समस्या का समाधान करेगीॅयदि किसी भी नागरिक को राज्य के किसी भी कोने में सड़क दुर्घटना या ट्रैफिक जाम से संबंधित कोई समस्या आती है या ऐसा कोई दृश्य दिखाई देता है, तो वेबसाइट **https ://gujhome. gujarat. gov.in/portal** पर फोटो और जानकारी अपलोड कर संबंधित जगह की जानकारी दे सकेगाॅकोई भी नागरिक ट्रैफिक संबंधी समस्या की जानकारी ईमेल आईडी **traffic grievance @gujarat .gov.in** पर भी दे सकता हैॅईमेल पर प्राप्त शिकायत के संबंध में भी समस्या के समाधान हेतु कार्यवाही की जायेगी। इन सभी माध्यमों से नागरिकों से प्राप्त यातायात संबंधी शिकायतों के निराकरण हेतु वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा सतत् निगरानी की जायेगी। इन माध्यमों से अब गुजरात के नागरिकों को अपनी यातायात समस्याओं का त्वरित और अधिक प्रभावी समाधान मिल सकेगा। राज्य यातायात शाखा द्वारा गुजरात के नागरिकों से इन नई सुविधाओं के व्यापक उपयोग का आह्वान किया गया है, ताकि राज्य की यातायात व्यवस्था में और सुधार किया जा सके और सड़क सुरक्षा बढ़ाई जा सके।

अहमदाबाद में बनेगा सबसे बड़ा फूड पार्क, अबू धाबी के क्राउन प्रिंस की भारत यात्रा के दौरान लिया गया फैसला

अहमदाबाद,10 सितम्बर,

गुजरात का सबसे बड़ा फूड पार्क अहमदाबाद मेंः तेजी से विकास और सुरक्षा के मामले में अहमदाबाद देश में सबसे आगे बनता जा रहा है। परिणामस्वरूप, बड़े उद्योग और विदेशी अहमदाबाद में निवेश बढ़ा रहे हैं। अहमदाबाद में भारत का सबसे बड़ा मॉल बनाने की तैयारी दिखाने के बाद अब यूएई ने मेगा फूड पार्क बनाने की घोषणा की है।

इसमेगाफूडपार्ककेलिए अहमदाबादकेबावला के पास गुंदनपुरा गांव कोचुनाजासकता हैजिसका परिचालन 2025 की दूसरी तिमाही में शुरू होने की संभावना है. इस संबंध में गुजरातसरकारऔरअबू धाबी डेवल पमेंट होल्डिंग कंपनी के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

गुजरात के इस मेगा फूड पार्क की मदद से राज्य के किसानों की कृषि उपज को सीधे मध्य-पूर्वी देशों में निर्यात करना संभव होगा। विदेशी निवेश भी बढ़ेगा. इसके अलावा आसपास के इलाकों की जमीन की कीमतें भी बढ़ने की संभावना है. यूएई का लुलु ग्रुप अहमदाबाद में 3.50 लाख वर्ग फुट क्षेत्रफल वाला देश का सबसे बड़ा मॉल बनाने के लिए भी निवेश करेगा। जिसके पीछे लगभग रु. 4000 करोड़ होंगे खर्च. जिससे 3000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा.

भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच हस्ताक्षरित पांच समझौता ज्ञापनों की सूची 1. एलएनजी की दीर्घकालिक आपूर्ति के लिए एडीएनओसी और आईओसीएल के बीच समझौता ज्ञापन 2. एडीएनओसी और आईएस पीआरएल के बीच समझौता 3. बराक परमाणु ऊर्जा संयंत्र के संचालन और रखरखाव के लिए ईएनईसी और एनपीसी आईएल के बीच भी समझौता ज्ञापन 4. एनर्जी इंडिया और एडीएनओसी के बीच अबू धाबी ऑनशोर ब्लॉक-वन के लिए उत्पादन रियायत समझौता 5. गुजरात में फूड पार्क के निर्माण के लिए गुजरात सरकार और पीजेएससी के बीच समझौता

अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अलनाहयान ने भारत का दौरा किया है, जिसमें पांच महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। क्राउन प्रिंसकेरूप में यह उनकी पहली भारत यात्रा है। क्राउन प्रिंस के साथ यूएई सरकारकेकई मंत्री और एक व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल भी आया है।

स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को लेकर अफवाह फैलाने पर केस दर्ज

अहमदाबाद (ईएमएस)ॅलौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की विश्व की सबसे विराट प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को लेकर अफवाह के मामले में पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई हैॅदरअसल नर्मदा जिले के केवडिया स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को लेकर एक्स पर तस्वीर पोस्ट की गई थीॅतस्वीर के साथ ही लिखा था 'कभी भी गिर सकती है, दरार पड़ना शुरू हो गई हैॅयह पोस्ट एक्स परॅउँइदीर्घ्ॅ नामक यूजर की ओर से 9 सितंबर को की गई थीॅइस तस्वीर में एक और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की पूरी फोटो है और दूसरी में पैर का हिस्सा बताया गया है, जिसमें दरार नजर आ रही हैॅहांलाकि यह तस्वीर फर्जी हैॅदूसरी ओर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में दरार की खबर आग की तरह सोशल मीडिया पर फैल गई और लोगों की प्रतिक्रिया सामने आने लगीॅएक यूजर ने कहा इसी तस्वीर को साझा कर लिखा 'स्टैच्यू पर स्पेस टेक्नोलोजी का असरॅ' इस घटना को लेकर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी प्राधिकरण ने एसओयू सुरक्षा पुलिस स्टेशन में झूठी अफवाहें फैलाने के लिए एक्स खाताधारक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। यह शिकायत एसओयू के डिप्टी कलेक्टर अभिषेक सिन्हा ने शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में झूठी खबरें फैलाकर लोगों में डर पैदा करने, शांति भंग करने की कोशिश करने, लोगों को गुमराह करने के लिए गलत प्रचार करने जैसे कृत्यों का जिक्र हैॅएक्स खाताधारक भारतीय न्यायिक संहिता की धारा 353(1)(बी) के तहत मामला दर्ज किया गया हैॅ

पीएम आवास योजना के तहत गुजरात में 9 साल में 14 लाख से ज्यादा आवासों का निर्माण

- शहरी क्षेत्र में 8.68 लाख और ग्रामीण इलाकों में 5.57 लाख से अधिक आवासों का निर्माण कार्य सम्पन्न

गांधीनगर (ईएमएस)ॅ''मेरा मकान कच्चा, मिट्टी का था। बरसात के दिनों में मकान की छत से पानी टपकता था। मैं और मेरा परिवार दिन-रात इस भय में जीते कि यह मकान कभी भी गिर जाएगा। मुझे मेरे परिवार की बहुत चिंता रहती। हालाँकि प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत मेरा मकान मंजूर होने के बाद मुझे पक्की छत वाला मकान और अन्य मूलभूत सुविधाएँ भी मिल रही हैं। अब मैं और मेरा परिवार बहुत खुश हैं।'' ये शब्द हैं गांधीनगर जिले की माणसा तहसील के खडात गाँव की निवासी किरणबेन राठौड़ के, जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत उनके सपनों का घर मिला है। देश में किरणबेन जैसे लाखों लोग हैं, जिनके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना वरदान सिद्ध हुई है। इसका श्रेय हमारे दूरदर्शी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को जाता है, जिन्होंने वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू की थी और इसके जरिये पिछले 9 वर्षों में अनेक लोगों को आवास सुविधा प्रदान कर उनके चेहरे पर मुस्कान लाई है।

गुजरात प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन में अग्रसर

भारत सरकार ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रभावशाली मार्गदर्शन अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को मकान की मूलभूत सुविधा मुहैया कराने तथा उनके जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) शुरू की थी, तो ग्रामीण क्षेत्र में भी बेघर लोगों को पक्का मकान मुहैया कराने के उद्देश्य से वर्ष 2016-17 में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) लागू की गई थी। गुजरात में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के सक्षम नेतृत्व में इस योजना का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन हो रहा है। राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत अब तक कुल 14.25 लाख आवासों का निर्माण पूर्ण किया गया है; जिनमें शहरी क्षेत्र में कुल 8.68 लाख से अधिक, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में 5.57 लाख से अधिक आवासों का निर्माण पूर्ण किया गया है। राज्य में निर्मित कुल आवासों के 64ऱ से अधिक आवास महिलाओं के नाम पर या तो संयुक्त स्वामित्व के नाम पर है। उल्लेखनीय है कि अगले सप्ताह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी गुजरात की यात्रा पर आ रहे हैं और इस यात्रा के दौरान वे पुनः एक बार गुजरात के नागरिकों को आवासों की भेंट देने जा रहे हैं।

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) का उद्देश्य शहरी क्षेत्र में गरीबों व मध्यम वर्ग के परिवारों को बुनियादी सुविधाओं से युक्त आवास वाजिब कीमत पर प्रदान करना है। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अंतर्गत गुजरात राज्य के कुल 7.64 लाख आवासों के लक्ष्य के सापेक्ष कुल 9.78 लाख आवास मंजूर किए गए हैं। इनमें लगभग 5 लाख 40 हजार से अधिक आवास महिलाओं के नाम पर या तो संयुक्त परिवार के नाम पर मंजूर किए गए हैं। इन स्वीकृत आवासों में से कुल 8.68 लाख आवासों का निर्माण पूर्ण किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के क्रेडिट लिंक सब्सिडी घटक अंतर्गत 6 लाख से भी अधिक लाभार्थियों को उनके प्रथम आवास पर लिए गए ऋण पर ब्याज सहायता का लाभ देने में गुजरात देश में अन्य राज्यों की तुलना में अग्रिम स्थान पर है।

इसके अतिरिक्त; केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2020 में आत्मनिर्भर भारत अभियान अंतर्गत अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेज (एआरएचसी) योजना अंतर्गत शहरी गरीबों व कामगारों को सस्ते किराए पर आवास प्रदान करने की घोषणा की गई थी। इस घोषणा के बाद तीन माह में ही गुजरात अपने सूरत शहर के सूरत नगरीय विकास प्राधिकारण (सुडा) क्षेत्र में निर्मित 393 आवासों को मॉडल-01 अंतर्गत किराए के मकानों में रूपांतरित कर प्रोजेक्ट की मंजूरी प्राप्त करने वाला देश का प्रथम राज्य बना है। ग्लोबल हाउसिंग टोक्नेलॉजी – इंडिया के लाइट हाउस प्रोजेक्ट के लिए केन्द्र सरकार द्वारा भारत से 6 राज्यों का चयन किया गया था, जिनमें गुजरात के राजकोट का चयन किया गया था। राजकोट में साइट हाउस प्रोजेक्ट अंतर्गत मोनोलिथिक कंक्रीट कन्स्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी का उपयोग कर ईडब्ल्यूएस-2 प्रकार के 39.77 वर्ग मीटर कारपेट एरिया वाले कुल 1,144 आवासों का निर्माण किया गया है।

अंबालाल पटेल की गुजरात में फिर एक बार भारी बारिश की भविष्यवाणी

अहमदाबाद (ईएमएस)ॅगुजरात में फिर एक बार भारी बारिश की भविष्यवाणी की गई हैॅमौसम के जानकार अंबालाल पटेल ने यह भविष्यवाणी करते हुए कहा है कि राज्य में 24 इंच जितनी बारिश हो सकती हैॅबता दें कि अगस्त के आखिर और सितंबर की शुरुआत में गुजरात के कई हिस्सों में भारी बारिश से बाढ़ से हालात हो गए थेॅजिसमें कृषि फसलों समेत भारी नुकसान हुआ थाॅऐसे में अंबालाल पटेल की फिर एक बार भविष्यवाणी सामने आई हैॅअंबालाल की मानें तो डीप डिप्रेशन के कारण गुजरात में आगामी तीन दिन भारी बारिश की संभावना हैॅखासकर पूर्व गुजरात में भारी बारिश की संभावना हैॅपंचमहल के हिस्सों में अतिभारी बारिश के चलते बाढ़ की स्थिति का निर्माण हो सकता हैॅ11 सितंबर से 13 सितंबर के दौरान गुजरात में मौसम का मिजाज बदलेगा और भारी बारिश होगीॅ15 से 17 सितंबर के दौरान पश्चिमी विक्षोभ के कारण गुजरात में 22 से 25 सितंबर के दौरान भारी बारिश होगीॅ

तीन शख्सों ने एक युवक को बुलाकर उसका अपहरण किया और बाद में उसे लूट लिया

अहमदाबाद (ईएमएस)ॅशहर से एक चौंका देनेवाली घटना सामने आई है, जिसमें सोशल मीडिया के जरिए संपर्क में आए शख्स को पहले बुलाया और बाद में उसका अपहरण कर लियाॅअपहरण के बाद उसके साथ मारपीट की और 40 हजार रुपए लूट लिएॅपीड़ित युवक की शिकायत के आधार पर बोडकदेव पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू की हैॅजानकारी के मुताबिक स्वप्निल देसाई, आयुष रबारी और आर्यन देसाई नामक तीन शख्सों ने लूट का प्लान बनाया और इसके लिए सोशल मीडिया का उपयोग कियाॅआरोपियों ने सोशल मीडिया के जरिए संपर्क में आए युवक अहमदाबाद के थलतेज के बागबान चौराहे के निकट बुलाया थाॅयुवक जब वहां पहुंचा तो कार में सवार आरोपियों ने उसका अपहरण कर लिया और उसके साथ मारपीट करते हुए उसे निर्जन क्षेत्र में ले गएॅजहां युवक से गूगल पे का पासवर्ड मांगाॅहांलाकि युवक के गलत पासवर्ड देने पर उसके साथ फिर मारपीट की और कहा कि अगर वह सही पासवर्ड देता है तो उसे जहां उठाया है, वहीं वापस छोड़ देंगेॅजिसके बाद युवक ने सही पासवर्ड दे दिया और आरोपियों ने क्यूआर कोड के जरिए स्कैन कर रु. 40000 ट्रांसफर करवा लिएॅजिसके बाद पीड़ित युवक ने बोडकदेव पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवा दीॅपुलिस ने बैंक एकाउंट नंबर के आधार पर आरोपियों के मोबाइल नंबर और पता हासिल कर तीन अलग अलग टीमें बनाईॅजिसके बाद पुलिस ने अहमदाबाद, मेहसाणा और गांधीनगर से तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लियाॅजांच में पता चला कि एक आरोपी कार की खरीद-बिक्री का काम करता है और दूसरा सरकारी नौकरी के लिए परीक्षा की तैयारी कर रहा हैॅ

मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल का शहरी नागरिकों की सुविधा में वृद्धि का एक और अहम निर्णय

गांधीनगर (ईएमएस)ॅमुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य के महानगर पालिका क्षेत्रों के विधायकों को उनके विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में सड़क संबंधित विभिन्न कार्यों के लिए प्रति विधायक दो करोड़ रुपए का अतिरिक्त अनुदान आवंटित करने का महत्वपूर्ण निर्णय किया है। उल्लेखनीय है कि महानगर पालिका क्षेत्र के विधायकों को शहरी विकास विभाग की ओर से उनके निर्वाचन क्षेत्र में स्थित कंक्रीट, डामर की नई सड़क, पुरानी सड़कों की रिसर्फेसिंग और जहां कंक्रीट और डामर रोड का निर्माण संभव नहीं है, वहां पेवर ब्लॉक बनाने के लिए अनुदान दिया जाता है। मुख्यमंत्री ने शहरी विकास विभाग के इस अनुदान के अलावा, ऐसे कार्यों के लिए सड़क एवं भवन विभाग के अनुदान से प्रति विधायक अतिरिक्त दो करोड़ रुपए के अनुदान को स्वीकृति दी है। राज्य में महानगर पालिका क्षेत्रों के 43 विधायकों को इस उद्देश्य से सड़क एवं भवन विभाग की ओर से कुल 86 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के इस शहरी नागरिकों की सुविधा में वृद्धि करने वाले निर्णय के परिणामस्वरूप महानगरों में मानसून के दौरान क्षतिग्रस्त हुई सड़कों की मरम्मत का कार्य जल्द शुरू किया जा सकेगा।

श्रीराम मोबिलिटी बुलेटिन : आगामी त्यौहारी सीजन की वजह से ट्रक किरायों में बढ़ोतरी, श्रीनगर सेक्टर में सुधार, भारत-बांग्लादेश सीमा फिर से खुली

अहमदाबादः श्रीराम मोबिलिटी बुलेटिन के ताजे संस्करण के अनुसार, अगस्त 2024 में ट्रक किराए में लगातार दूसरे महीनेमें वृद्धि देखि गई, जो किरयोंमें लगातार वृद्धि जारी रहने का संकेत है। त्योहारी सीजन के आगमन के साथ-साथ चुनाव के बाद की गतिविधियों में वृद्धि ने विभिन्न परिवहन मार्गों पर मांग को काफी हद तक बढ़ा दिया है।

विशेषतः, भारत-बांग्लादेश सीमा क्षेत्र में ट्रकोंके के उपयोग में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, जो पिछले 40ऱ से बढ़कर लगभग 60ऱ हो गया है। भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार गतिविधियों के फिर से शुरू होने से विशेष रूप से कोलकाता-गुवाहाटी-कोलकाता मार्ग पर ट्रक किराये में 3.0ऱ की उच्चतम वृद्धि दर्ज की गई है। दिल्ली-कोलकाता-दिल्ली और दिल्ली-हैदराबाद-दिल्ली रूट पर भी भाड़े में क्रमशः 2.7ऱ व 2.3ऱ की बढ़ोतरी हुई। श्रीनगर क्षेत्र में सेब की फ़सल और चुनाव संबंधी कामों में के चलते निकली मांग से ट्रक का भाड़ा अगस्त माह में 10ऱ तक बढ़ गया। वायनाड क्षेत्र में कई ट्रक पुनर्वास कार्य में लगे हुए होने के कारण ट्रकों की संख्या कम हो गयी है जिसकी वजह से ट्रक भाड़े में वृद्धि देखी गई।

श्री. वाई. एस. चक्रवर्ती, एमडी और सीईओ, श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड, ने बुलेटिन पर टिप्पणी करते हुए कहा, 'त्यौहारी सीजन नजदीक आ रहा है। कंपनियां उत्पादन और सप्लाई दोनों में तेजी लाने में लगी हैं। इसलिए सभी प्रमुख रूट में ट्रक भाड़े में बढ़ोतरी हो रही है। श्रीनगर रूट पर सेब के सीजन और चुनाव पूर्व गतिविधियों के चलते भाड़े में इजाफा देखा गया। इसके साथ ही भारत-बांग्लादेश व्यापार फिर से प्रारंभ होने से इससे लगे रूट पर ट्रक की डिमांड के साथ ट्रक के भाड़े में तेजी आई। हालांकि हाल ही में गुजरात में आई बाढ़ लॉजिस्टिक क्षेत्रके लिए बड़ी चुनौती बन रही है। आंध्र और तेलंगाना क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति को देखतेहुए,अभीयहअंदाजा लगाना मुश्किल है की इस प्रभाव से उभरने में उन्हें कितना समय लगेगा और वहांकी परिस्थिति पर हम सतर्कता से नज़र रखे हुए है।'

अवीवा इंडिया ने अपने अवीवा सिग्नेचर इंक्रीजिंग इनकम प्लान से रिटायरमेंट सिक्योधरिटी को नए ढंग से परिभाषित किया है

नई दिल्ली, 10 सितंबर 2024: भारत के सबसे भरोसेमंद निजी जीवन बीमा कंपनी, अवीवा लाइफ इंश्योरेंस ने अवीवा सिग्नेचर इंक्रीजिंग इनकम प्लान - एक नॉन-लिंक्ड, गैर-भागीदारी, जीवन बीमा बचत योजना **(UIN: 122N1 58V01)** शुरु करने की घोषणा की है। इस प्लान को खास तौर पर रिटायरमेंट के बाद गारंटीड एवं बढ़ती आय प्रदान करने और ग्राहकों को उनके जीवन के सुनहरे वर्षों में स्वतंत्र रूप से क्ष्जीवन जीने में मदद करने के लिए बनाया गया है।

बढ़ती जीवन प्रत्याशा और जीवन यापन के बढ़ते खर्च को देखते हुए रिटायरमेंट के बाद वित्तीय सुरक्षा इतनी महत्वपूर्ण कभी नहीं थी, जितनी आज हो गई है। अवीवा सिग्नेचर इंक्रीजिंग इनकम प्लान इन चुनौतियों का स्पशष्टन समाधान प्रस्तुीत करता है, नए फीचर्स देता है, जो इसे बाजार में सबसे अलग खड़ा करते है।

यह योजना हर तीसरे पॉलिसी वर्ष में मासिक आय में 15ऱ की वृद्धि करके बढ़ती हुई मंहगाई से राहत प्रदान करती है, अर्थात् समय के साथ, मुद्रास्फीति के के अनुसार पेआउट भी बढ़ता है, इस प्रकार यह पॉलिसीधारक की क्रय शक्ति को बनाए रखती है।

दिप इंडस्ट्रीज लिमिटेड को ओएनजीसी से प्रोडक्शन एनहैंसमेंट ऑपरेशन्स के लिए रू. 1,402 करोड़ का ऑर्डर मिला

अहमदाबादः ऑयल और गैस फील्ड ऑपरेशन्स के लिए लीडिंग इंटीग्रेटेड सॉल्यूशंस प्रोवाइडर, दिप इंडस्ट्रीज लिमिटेड (डीआईएल) ने ऑइल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन (ओएनजीसी) से रू.1,402 करोड़ रुपए का एक ऑर्डर मिलने की घोषणा की है। यह कॉन्ट्रैक्ट ओएनजीसी के राजमुंदरी एसेट के मैच्योर फील्ड्स में प्रोडक्शन एनहैंसमेंट ऑपरेशन्स के लिए है और इसकी अवधि 15 साल है। यह कंपनी को दिया गया अब तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, जो इसकी वर्तमान ऑर्डर बुक से दोगुनी से भी अधिक है। 30 जून, 2024 तक, कंपनी की ऑर्डर बुक रू. 1,246 करोड़ थी।

इस महत्वपूर्ण जीत पर टिप्पणी करते हुए, दिप इंडस्ट्रीज लिमिटेड के **MD,** पारस सावला ने कहा, ''हम इस ऐतिहासिक उपलब्धि की घोषणा करते हुए रोमांचित हैं क्योंकि हम प्रोडक्शन एनहैंसमेंट कॉन्ट्रैक्ट (पीईसी) में अपनी एक्सपर्टाइज को एक्सटेंड कर रहे हैं। यह स्ट्रैटेजिक विन हमें इवॉल्विंग ऑइल एंड गैस सर्विसेज वैल्यू चेन में तेजी से अभिन्न भूमिका निभाने के लिए तैयार करती है। इस क्षेत्र में तीन दशकों से अधिक के अनुभव के साथ, दीप इंडस्ट्रीज प्रूवन, एडवान्स्ड टेक्नीक्स के डिप्लॉयमेंट के माध्यम से ऑइल एंड गैस प्रोडक्शन को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए वेल इक्विप्ड है।

प्रोडक्शन एनहैंसमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स **(PEC)** का उद्देश्य हाइड्रोकार्बन का उत्पादन बढ़ाना है। राजमुंदरी एसेट में, ओएनजीसी कॉन्ट्रैक्ट एरिया से हाइड्रोकार्बन भंडार को इस तरह से डेवलप करना चाहता है जिससे सेफ और एफिशिएंट ऑपरेटिंग प्रैक्टिसेज और सुटेबल टेक्निक और टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन से वर्तमान उत्पादन और हाइड्रोकार्बन की अल्टीमेट रिकवारी में सुधार हो।

सौर ऊर्जा का उपयोग करने के लिए राजकोट रेल मंडल की पहल

पश्चिम रेलवे का राजकोट मंडल 2030 तक ठनेट जीरो कार्बन एमिटरठ प्राप्त करने के भारतीय रेलवे के लक्ष्य के लिए प्रतिबद्ध है। राजकोट मंडल रेल प्रबंधक श्री अश्वनी कुमार के अनुसार पर्यावरण संरक्षण की प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाते हुए, राजकोट मंडल हरित और नवीकरणीय ऊर्जा की दिशा में बड़े कदम उठा रहा है। राजकोट मंडल अपनी बिजली आवश्यकताओं के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग कर रहा है और नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। सितंबर-2024 तक राजकोट मंडल के 18 रेलवे स्टेशनों पर और 7 रेलवे कार्यालय भवनों में 539 किलोवाट क्षमता के सौर पैनल लगाए जा चुके हैं। इससे राजस्व की भी काफी बचत हुई है। यह लगभग 21 हजार पेड़ों की कार्बन अवशोषण क्षमता के बराबर है। पिछलेवित्तवर्ष 2023-24 में राजकोट मंडल पर सौर पैनलों ने 454989 केडबल्यूएच (यूनिट) बिजली पैदा की है, जो 364 टन से अधिक कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के बराबर है और इसके परिणामस्वरूप कुल 27.18 लाख रुपये की बचत हुई है। चालू वित्त वर्ष 2024-25 (अगस्त तक) के दौरान, 282666 केडबल्यूएच (यूनिट) बिजली का सौर ऊर्जा उत्पादन हुआ, जो 226 टन से अधिक कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के बराबर है और इसके परिणामस्वरूप कुल 18.91 लाख रुपये की बचत हुई है। इसके अलावा, राजकोट मंडल ने हरित ऊर्जा संसाधनों के हिस्से के रूप में सौर जल हीटर, एलसी गेटों पर सौर पैनल उपलब्ध कराए हैं। इसके अलावा, राजकोट मंडल कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के राष्ट्र केमिशन को प्राप्त करने के लिए अधिकतम सीमा तकसभी भवनों में सौर संयंत्र स्थापित करने की योजना बना रहा है।

राष्ट्रीय पोषण सप्ताहः आयोडीन क्रांति में टाटा नमक की पहल

10 सितंबर, 2024: 1983 में लॉन्च होने के बाद से, टाटा नमक ने भारत में आम जनता को प्रभावित करने वाली आयोडीन की कमी जैसी प्रमुख स्वास्थ्यचुनौतीके खिलाफ निरंतर अभियान चलाया है। देश के पहले आयोडीन युक्त नमक ब्रैंड के तौर पर, टाटा नमक ने गुणवत्ता के नए मानक स्थापित करते हुए आयोडीन युक्त नमकको देशभर में हर घर तकपहुंचाया है।कई वर्षों में, टाटा नमक भरोसे और सेहत का पर्याय बन चुका है और आज लाखों भारतीय परिवारों की रोज़मर्रा की जिंदगी का हिस्सा है।

आयोडीन, जो कि एक आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व (माइक्रोन्यूट्रिएंट) है, सामान्य विकास, थाइरॉयड तथा मस्तिष्क की कार्यप्रणाली के लिए जरूरी है। आयोडीन की कमी की वजह से, खासतौर से बच्चों में, गॉइटर और विकास में देरी जैसी स्वास्थ्य समस्याएं पैदा हो सकती हैं। इसलिए आयोडीन युक्त नमक के बारे में लगातार जागरूकता बढ़ाने और इसके सेवन पर ज़ोर देने की आवश्यकता है।

टाटा नमक इस चुनौती से निपटने के लिए लगातार अग्रणी बना हुआ है और सुनिश्चित करता है कि आयोडीन की सही मात्रा नमक में हो। इन प्रयासों का ही नतीजा है कि आयोडीन की कमी से पैदा होने वाले डिसऑर्डरों (आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स) में कमी आयी है, और भारत में पब्लिक हेल्थ, खासतौर से बच्चों की सेहत में, जिनके मानसिक विकास के लिए आयोडीन काफी महत्वपूर्ण होता है, सुधार आया है।

पश्चिम रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी श्री सचिन शर्मा ने लद्दाख में 122 किलोमीटर की सिल्क रूट अल्ट्रा मैराथन पूरी की

पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक के सचिव श्री सचिन अशोक शर्मा (**IRTS** 2008) ने 5 से 8 सितंबर, 2024 तक आयोजित हुई चुनौतीपूर्ण लद्दाख मैराथन 2024 में भाग लिया। उन्होंने 122 किलोमीटर की सिल्क रूट अल्ट्रा मैराथन की एंडयूरेंस दौड़ में भाग लिया और इस चुनौतीपूर्ण दौड़ को 20 घंटे और 39 मिनट में पूरा किया।

पश्चिम रेलवे के जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार श्री शर्मा ने 6 सितंबर, 2024 को सिल्क रूट अल्ट्रा मैराथन को 20 घंटे और 39 मिनट में सफलतापूर्वक पूरा किया। यह दौड़ 5 सितंबर, 2024 को 19.00 बजे क्यागर गांव से शुरू हुई, जो कि नुब्रा घाटी में सियाचिन बेस कैंप के दक्षिण में स्थित है और श्री शर्मा 6 सितंबर, 2024 को 15.39 बजे फिनिश लाइन पर पहुंचे।

सिल्क रूट अल्ट्रा मैराथन (122 किमी) एक हाई एल्टीटयूड अल्ट्रा-मैराथन है, जो समुद्र तल से लगभग 10,500 फीट की ऊंचाई **(ASL)** से शुरू होती है, खारदुंग ला को पार करती है जो 18,000 फीट **ASL** पर है और अंत में लेह मार्केट (10,500 फीटॅएथ) में समाप्त होती है, जिससे यह दौड़ दुनिया की सबसे कठिन पैदल दौड़ में से एक बन जाती है। इस वर्ष केवल 50ऱ प्रतिभागी ही इस कठिन दौड़ को पूरा कर सके हैं। श्री शर्मा इस हाई एंडयूरेंस दौड़ में भाग लेने और इसे सफलतापूर्वक पूरी करने वाले एकमात्र रेलवे अधिकारी और लोकसेवक हैं।

इससे पहले, श्री शर्मा ने 2022 में 42 किलोमीटर की लद्दाख फुल मैराथन 2023 में 72 किलोमीटर की खारदुंग ला चैलेंज और 42 किलोमीटर की लद्दाख फुल मैराथन, दक्षिण अफ्रीका में आयोजित कॉमरेड्स मैराथन (86 किलोमीटर) के अलावा देश भर में कई अन्य अल्ट्रा और अन्य मैराथन और ट्रायथलॉन में भी भाग लिया है। पश्चिम रेलवे श्री शर्मा को उनकी इस उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए बधाई देता है और आगामी दौड़ के लिए उनकी सफलता की कामना करता है।

पश्चिम रेलवे-वडोदरा मंडल

ओपन 'ई' टेंडर नोटिस

निविदा सं.: EL/TRD/Tender/23-24/22R5, भारत के राष्ट्रपति की ओर से मंडल रेल प्रबंधक (कर्षण वितरण) वडोदरा द्वारा निम्नलिखित कार्य के लिये निविदाएँ आमंत्रित की जाती है। **क्र. सं. 1- निविदा सं.: EL/TRD/Tender/23-24/22R5, कार्य का नाम:** वडोदरा डिवीजन के सूरत-गेरातपुर, वडोदरा-गोधरा और वडोदरा-डभोई अनुभाग में रोड अंडर ब्रिज (आरयूबी) के प्रावधान और पोर्टल/टीटीसी के ड्रॉप आर्म (डीए/बूम) पर नंबर प्लेटों के प्रावधान के कारण मौजूदा ओएचई में संशोधन। **कार्य की अनुमानित लागत (₹ में):** ₹ 1,26,31,886/- **बोली प्रतिभूति (₹ में):** ₹ 2,13,200/- **निविदा की राशि एवं कार्य समापन की अवधि:** कार्य समापन की अवधी 12 माह, **निविदा की समय सारणी:** निविदा बंद होने का दिनांक एवं समय 08/10/2024 को 15.00 बजे। **वेबसाइट विवरण और सूचना का लोकेशन जहां पूर्ण विवरण देखा जा सकता है तथा कार्यालय का पता विवरण जानकारी के किए:** वेबसाइट विवरण **www.ireps.gov.in** मंडल रेल प्रबंधक (कर्षण वितरण) पश्चिम रेलवे, प्रतापनगर, वड़ोदरा - 390 004

(EL/TRD/Tender/23-24/22R5 dtd. 06/09/2024) 170

हमें लाइक करें: facebook.com/WesternRly

मालिक-मुद्रक- प्रकाशक व संपादकः लक्ष्मीचंद जी. अग्रवाल द्वारा, ब्रिजाशा ऑफसेट, जी.एम. कम्पाउन्ड, सरसपुर, अहमदाबाद -380018 में मुद्रित करवा कर वहीं से प्रकाशित किया। प्रातः कालीन E-mail : janhitaishi@yahoo.co.in फोनः 079-22921482 Mob.9375504122 , 9327086467 R.N.I. 63177/ 95